सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivahan_Vishesh
RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 143, नई दिल्ली । शनिवार, 03 अगस्त 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी।

03 एलजी साहब ने कई बार जनता के हक की आवाज सुनी है- दिलीप पांडे
06 बढ़ती आबादी और घटते संसाधन
08 एक शराबी पिता द्वारा अपने ढाई साल के बेटे को पांच हजार रुपये में बेचा

वाहनों पर एचएसआरपी लगाने की अंतिम तिथि दस अगस्त तक बढ़ाई, इसके बाद 10 हजार तक का चालान

संजय बाटला

नई दिल्ली । परिवहन विभाग के अनुसार वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया है पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई रखी गई है ट्रांसपोर्ट और रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से एचएसआरपी लगवाने की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है इसके लिए परिवहन विभाग ने बुधवार को आदेश जारी किए हैं यदि आप पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगवाते हैं तो 10 अगस्त के बाद आपको ₹10000 तक का चालान देना होगा ।परिवहन विभाग के आदेश अनुसार अब पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ा दी है वाहन मालिक 10 अगस्त तक एचएसआरपी नंबर प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद बुकिंग स्लिप दिखाने पर भी चालान से बच सकेंगे 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत पुराने वाहनों पर एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई रखी गई थी जिसे लोगों की सुविधा के लिए बढ़कर 10 अगस्त कर दिया है ।तय तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए विभाग के निर्धारित पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने वाले वाहन चालकों पर 5000 से 10000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा अभ्यर्थी चालान से बचने के लिए निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन जरूर करें और अपने वाहनों पर लगवा लें ।सरकार की ओर से 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया है इसके बावजूद कई वाहन चालक अपने वहां पर नंबर प्लेट नहीं बदल रहे हैं आपको बता दें कि एक अप्रैल 2019 से पहले उपलब्ध नंबर प्लेटों के साथ छेड़छाड़ करना आसान था इन्हें आसानी से हटाया और बदला जा सकता है इस कारण इनके चोरी होने पर ट्रैक करना भी मुश्किल हो जाता है ।हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अल्युमिनियम से बनी एक प्लेट होती है इन्हें कम से कम वन टाइम यूज्ड स्नैप-ऑन-लॉक के जरिए गाड़ी के फ्रंट और बैक में लगाया जाता है इन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता और ना ही एक बार हटाने के बाद दूसरी नंबर प्लेट लगाई जा सकती है

HSRP में लिखे अंक को अक्षरों और बॉर्डर पर एक हॉट स्टैंप वाली फिल्म लगाई जाती है इसमें 45 डिग्री के एंगल पर इंडिया लिखा होता है प्लेट पर अंक और अक्षर का साइज 10mm और एक खास फोंट होता है लाइट पड़ने पर अंक और अक्सर चमक उठाते हैं और सीसीटीवी कैमरे में आसानी से कैप्चर हो जाते हैं ।हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में ऊपर बाय कोने पर नीले रंग में अशोक चक्र का हॉट स्टेप्ड क्रोमियम बेस्ट होलोग्राम होता है इसके नीचे बाएं कोने पर 10 अंक का सीक्रेट कोड लेजर से लिखा होता है जो यूनिवर्सल होता है यह नंबर एक ही गाड़ी के फ्रंट और रियर नंबर प्लेट में अलग-अलग होता है इस सीक्रेट कोड में गाड़ी से जुड़ी सारी डिटेल्स जैसे चेसिस और इंजन नंबर, परचेसिंग डेट, गाड़ी का मॉडल, डीलर और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी आदि होता है ।हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट दुपहिया वाहन के लिए 425 रुपए कार के लिए 695 रुपए, मध्य एवं भारी वाहन के लिए 730 रुपए और ट्रैक्टर कृषि कार्य से जुड़े वाहनों के लिए 495 रुपए में मिल जाती है ।एचएसआरपी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की आवेदन प्रक्रियासबसे पहले आपको सियाम पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट siam.in पर जाना है इसके बाद आपको अपने वाहन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर आदि जानकारी के साथ रजिस्ट्रेशन करना है इसके बाद अपने वाहन निर्माता कंपनी, जिले और सबसे नजदीकी वाहन डीलर का चयन करने के बाद एचएसआरपी प्लेट के लिए शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना है ।इसके बाद अपना स्टॉल बुक कर लेना है अपने रिकॉर्ड के लिए भुगतान की रसीद प्राप्त कर लेनी है और आपके पंजीकरण की सूचना मोबाइल नंबर पर भी प्राप्त हो जाएगी इसके बाद निर्धारित तिथि पर आप चुने गए नजदीकी डीलर के पास जाकर एचएसआरपी ले सकते हैं इसके लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट के अलावा किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं देना होगा एक बार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के बाद हमेशा के लिए वैध है।

देश को जल्द मिलेंगे 8 हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर, कैबिनेट से मुहर के बाद पीएम मोदी ने गिनाए इसके फायदे

परिवहन विशेष न्यूज

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 50655 करोड़ रुपये की लागत से 936 किलोमीटर लंबी आठ महत्वपूर्ण नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। पीएम मोदी ने कहा कि नेशनल हाई–स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी से हमारे आर्थिक विकास पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा साथ ही रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा फैसला हुआ है। कैबिनेट ने 50,655 करोड़ रुपये की लागत से 936 किलोमीटर लंबी आठ महत्वपूर्ण नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

पीएम मोदी ने क्या कहा ?

कैबिनेट के फैसले का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने एक्स पर कहा, 'भारत के बुनियादी ढांचे में परिवर्तनकारी बढ़ावा ! नेशनल हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी से हमारे आर्थिक विकास पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा साथ ही रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।'

इन शहरों को होगा फायदा

देश के अलग-अलग कोनों में बनने जा रही इन सड़कों से न सिर्फ लोगों के समय के बचत होगी बल्कि कई शहरों की दूरी भी घट जाएगी। साथ ही ये ईंधन की बचत करने में भी मदद देंगे। इन नए कॉरिडोर से कानपुर-लखनऊ, अयोध्या, आगरा-ग्वालियर, खड़गपुर-मोरेग्राम, रायपुर-रांची, अहमदाबाद, पुणे, नाशिक, अयोध्या और गुवाहाटी को फायदा पहुंचेगा।

किन परियोजनाओं पर होगा काम ?

उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अनुमानित 4.42 करोड़ दिन का रोजगार पैदा होंगे। परियोजनाओं में 6-लेन कानपुर रिंग रोड, 4-लेन अयोध्या रिंग रोड, 6-लेन आगरा-ग्वालियर नेशनल हाई-स्पीड कॉरिडोर, 4-लेन खड़गपुर - मोरग्राम नेशनल हाई-स्पीड कॉरिडोर, 6-लेन थराद - दीसा - मेहसाणा- अहमदाबाद नेशनल हाई-स्पीड कॉरिडोर और रायपुर-रांची नेशनल हाईस्पीड कॉरिडोर के पत्थलगांव और गुमला के बीच 4-लेन खंड शामिल हैं।

सम्पादक के नाम पत्र : विकास और समय की बचत को परे रखें

विकास और समय की बचत को दृष्टीगत रखते हुए सड़कों का निर्माण पहाड़ों को काटकर किया जा रहा हैं। जिसके कारण भूस्खलनके मामले बढ़ते जा रहें हैं। भूस्खलन ढलानों पर सतह के तेजी से खिसकने की ऐसी अवस्था है, जहाँ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में चट्टान, मलबा और मिट्टी गिर जाते हैं। उनकी एकरूपता को चोट पहुँचने पर वे भार छोड़ देती हैं। इस कारण भीषण घटनाएँ हो रहीं हैं। इसका समाधान निकाला जाना चाहिए।

संजय एम. तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
31, संजय नगर, इंदौर (मध्यप्रदेश)

25 मोहल्ला बसें माह के अंत में सड़कों पर दौड़ेंगी

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली । दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मोहल्ला बस का पहला बेड़ा माह के अंत तक सड़कों पर उतरेगा। शुरू में 50 बसें शामिल की जाएगी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2025 तक 2180 बसें सड़कों पर उतरेंगी। इसके लिए तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। इन बसों का किराया दिल्ली सरकार की एसी बसों के जैसा 10, 15, 20 व 25 रुपये रहेगा। वहीं, महिलाओं को किराया नहीं देना होगा।

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के अनुसार, नौ मीटर लंबी बसों को छोटी गलियों व भीड़भाड़ वाले इलाकों में प्रवेश करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये उन मार्गों पर चलेंगी जहां डीटीसी की 12 मीटर लंबी बसें नहीं चल सकती हैं। मोहल्ला बसें मेट्रो स्टेशनों जैसे प्रमुख परिवहन स्थानों को भी बेहतर ढंग से जोड़ेंगी। इनका रूट 10 किमी से कम दूरी तक होगा। इससे लोगों को कम समय में बसें मिल सकेंगी।

45 मिनट में हो जाएगी चार्ज

मोहल्ला बस 196 किलोवाट की कुल क्षमता वाले छह बैटरी पैक से सुसज्जित हैं। यह 45 मिनट की चार्जिंग के साथ 200 किमी की रेंज प्रदान करेंगी। बसों में 23 यात्री सीटें और 13 यात्रियों के खड़े होने की क्षमता है। इसमें 25% सीटें (6 सीटें) गुलाबी रंग की हैं, जो महिला यात्रियों के लिए आरक्षित हैं।

पार्किंग और रखरखाव के लिए बनाए 16 डिपो

पूर्वी जोन

गाजीपुर डिपो में 60 मोहल्ला बसें होंगी।

ईस्ट विनोद नगर में 180 मोहल्ला बसें होंगी।

पश्चिम जोन

द्वारका मुख्य डिपो में 40 मोहल्ला बसें होंगी।

द्वारका सेक्टर 2 डिपो में 180 मोहल्ला बसें होंगी।

केशोपुर डिपो में 180 मोहल्ला बसें होंगी।

पीरागढ़ी डिपो में 135 मोहल्ला बसें होंगी।

शादीपुर डिपो में 230 मोहल्ला बसें होंगी।

द्वारका सेक्टर-9 डिपो में 20 मोहल्ला बसें होंगी।

दक्षिणी जोन

कुशक नाला डिपो में 350 मोहल्ला बसें होंगी।

अंबेडकर नगर डिपो में 180 मोहल्ला बसें होंगी।

उत्तरी जोन

मुंडका डिपो में 60 मोहल्ला बसें होंगी।

नांगलोई डीएमआरसी में 60 मोहल्ला बसें होंगी।

नांगलोई डीटीसी डिपो में 180 मोहल्ला बसें होंगी।

रिठाला डिपो में 70 मोहल्ला बसें होंगी।

कोहाट एन्क्लेव डिपो में 35 मोहल्ला बसें होंगी।

नरेला बस डिपो में 180 मोहल्ला बसें होंगी।

उदाहरण द्वारा नेतृत्व: उद्योग विशेषज्ञों और प्रोफेसरों द्वारा सुंदर आपूर्ति श्रृंखला सम्मेलन

- डॉ. लॉजिस्टिक्स

उद्योग विशेषज्ञों और प्रोफेसरों द्वारा आयोजित एक प्रेरणादायक आपूर्ति श्रृंखला सम्मेलन में युवाओं को रसद और आपूर्ति श्रृंखला उद्योग की बेहतर समझ दी गई। इस सम्मेलन ने न केवल उद्योग के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया बल्कि वास्तविक जीवन के अनुभवों और केस स्टडीज के माध्यम से प्रतिभागियों को व्यावहारिक ज्ञान भी प्रदान किया। भविष्य के पेशेवरों को तैयार करने के उद्देश्य से, इस सम्मेलन ने युवाओं में आत्मविश्वास और कौशल विकास को प्रोत्साहित किया, जिससे वे उद्योग में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित हुए।

ग्रेटर नोएडा स्थित GIMS संस्थान में हाल ही में एक अद्वितीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन के क्षेत्र में अग्रणी विशेषज्ञों ने छात्रों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में सप्लाई चेन और मैनेजमेंट कोर्स कर रहे छात्रों को शिक्षित और प्रेरित करने के उद्देश्य से डॉ. अंकुर शरण, एक सप्लाई चेन प्रोफेशनल और हार्ड कोर लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ, ने छात्रों के साथ अपनी बहुमूल्य जानकारियाँ साझा कीं।

डॉ. अंकुर शरण ने सप्लाई चेन की मांग और इसके भारत को उभरती शक्ति बनाने में योगदान पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे सप्लाई चेन का महत्व हमारे देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। इसके साथ ही, रोहित किशोर ने ई-कॉमर्स के अपने अनुभव साझा किए और श्री सचिन शर्मा ने सप्लाई चेन के तकनीकी पहलुओं पर प्रकाश डाला। छात्रों को समझाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि वे अपनी कक्षाओं में किसी भी लेख या पुस्तक को पढ़ते समय उसकी प्रासंगिकता को समझ सकें और औद्योगिक विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में सर्वोत्तम अनुभव प्राप्त कर सकें, जैसा कि डॉ. अंकुर शरण ने 'डॉ. लॉजिस्टिक्स' फोरम के माध्यम से बताया।

प्रबंधन की टीम ने इस प्रयास की सराहना की और कहा कि छात्रों को इंडस्ट्री के विशेषज्ञों से मिलने का यह सुनहरा अवसर उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाएगा।

श्री मनीष सहाय ने छात्रों के साथ ICD संचालन के बारे में अपने शिपिंग और संचालन अनुभव साझा किए, जिससे छात्रों को वास्तविक जीवन के अनुभवों से सीखने का मौका मिला।

GMIS प्रबंधन की टीम में निम्नलिखित प्रमुख व्यक्ति उपस्थित थेः

श्री विजय शुक्ला (निदेशक CRC)

डॉ. भूपेंद्र कुमार सोम (निदेशक GIMS)

श्री अमित रंजन (ऑपरेशंस हेड)

श्री सुधांशु कुमार (सहायक प्रोफेसर - सप्लाई चेन)

डॉ. इमाद अली (प्रोफेसर एवं एरिया चेयर - ऑपरेशंस एवं सप्लाई चेन मैनेजमेंट)

इस आयोजन ने छात्रों को उद्योग के विशेषज्ञों से सीधे संवाद करने का अवसर प्रदान किया और उनके व्यावसायिक कौशल को निखारने में मदद की। 'डॉ. लॉजिस्टिक्स' के माध्यम से इस तरह के प्रयास भविष्य में भी जारी रहेंगे, जिससे छात्रों को उद्योग के नवीनतम रुझानों और प्रथाओं से अवगत कराया जा सके।

“परिवहन विशेष का प्रयास है कि डॉ. लॉजिस्टिक्स जैसे फोरम और संस्थानों के ऐसे कॉन्क्लेव द्वारा हम हिंदी भाषा में सुगमता और सरलता से युवाओं को सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स एवं परिवहन के बारे में व्यापक पैमाने पर जानकारी दें और उन्हें भारत के गौरवशाली भविष्य के लिए आज से तैयार करें। इन आयोजनों का उद्देश्य है कि छात्रों को उद्योग के विशेषज्ञों के अनुभव और ज्ञान से जोड़कर उनके व्यावसायिक कौशल को निखारा जाए। इस प्रकार के कार्यक्रम न केवल छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करते हैं बल्कि उन्हें व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी प्रशिक्षित करते हैं, जिससे वे अपने करियर में सफलता प्राप्त कर सकें। परिवहन विशेष इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है और युवाओं को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

कविता

संजय एम. तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
98260 25986
taranekar9@gmail.com

बरस जाओ झमाझम

कब तक तरसाओगे
बरस भी जाओ मेघराज
अभी-भी कंठ है रीता.
सबकी हो रही फ़ज़ति.
तेज़ हवाओं के साथ
रोज़ दगा दे रही घटाए.
अब रिमझिम-रिमझिम से
नहीं चलनेवाला काम.
बताओ बरखा रानी
क्यों रूठी हो हमसे.
क्या रेनकोट, क्या छाता
अब पन्नी बेचनेवाला भी
सूखा ही चला जाता.
सब ताक रहें हैं कबसे
दुआएँ कर रहें रब से.
बरस जाओ झमाझम
खुश हो जाए हम-तुम.

वाह-वाह जया

संसद में अक्सर
भड़क जाती हैं जया.
उनको बॉलीवुड वालों पर
आती नहीं हैं दया.
पहले रवि किशन
हो गए थे शिकार.
उन्हें नहीं मिल पाया
समर्थन अपार.
अबकी बार तो मानो
हद ही हो गई,
जया अपने पति
अमिताभ का नाम
जोड़ने से ही भड़क गई.
न जाने कौनसी
स्त्रियों के अस्तित्व की
लड़ाई लड़ रहीं हैं.
अपने पति पर ही
भारी पड़ रहीं हैं.
राज्यसभा के मंच का
वे ले रहीं हैं लाभ,
अब और न जाने क्या
भविष्य में करेंगी बयां.
वाह वाह जया-2

बीमारियाँ और आबादियाँ

न मैं हार रहा
और न बीमारियाँ.
ये ज़न्दिगी की,
लगी हैं कारगुज़ारियाँ.
आएं चाहे जितनी,
कम न हो दुशवारियां.
मैं हूँ भले कमज़ोर,
कर लूँगा मज़दूरियाँ.
अभी उठानी हैं मुझे,
अपनों की जिम्मेदारियां.
फ़रि चाहे बिक जाए
कमाया हैं जो कुछ,
हो जाए बरबादियाँ.
मैं अब भी सोचता हूँ
कैसे होगा सब कुछ
कब हो पाऊँगा खड़ा
समय विकट है बड़ा.
और उम्मीद है मुझे
रब ने सोचा ही होगा,
वो लौटाएगा आबादियाँ.

मनु भाकर इतिहास की बेटी

पांच स्वर्ण पदक अपने नाम करने वाली हिमा दास पहली भारतीय महिला हैं, यह उपलब्धि हिमा ने मात्र 19 वर्ष की आयु में हासिल की । हिमा दास को धींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। हिमा शुरुआती जीवन में फुटबॉलर बनना चाहती थी, लेकिन पीटी टीचर ने उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें एथलेटिक बनने

निशानेबाज बिटिया मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में वह कर दिखाया है, जो अभूतपूर्व, अप्रत्याशित, अतुलनीय और अनिर्वचनीय है। एक ही खेल के दो प्रारूपों में लगातार दो कांस्य पदक जीत कर मनु ने कई इतिहास लिख दिए हैं। मनु के साथ सरबजोत सिंह भी मिश्रित खेल की अप्रतिम उपलब्धि के सूत्रधार हैं, लिहाजा देश के बेटे-बेटी को साझा शाबाश'! मनु 10 मीटर एयर पिस्टल की निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। यह राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय गौरव भी मनु के हिस्से आया है कि एक ही ओलंपिक में, एक ही खेल की दो शैलियों में, दो ओलंपिक पदक जीतने वाली भी प्रथम महिला खिलाड़ी बन गई हैं। देश की संप्रभु आजादी के 77 सालों में मनु भाकर इस तरह ओलंपिक पदकवीर बनने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। मनु की यह सफलता 'हैट्रिक' में भी तबदील हो सकती है, क्योंकि उन्हें 2 अगस्त को 25 मीटर रैपिड निशानेबाजी में भी भाग लेना है। खेल की यह शैली मनु को सर्वाधिक प्रिय है। विश्व चैंपियनशिप और एशियाड में खेल की इसी शैली में मनु स्वर्ण पदक जीत चुकी है। विश्व कप में इस 'होनहार बेटी' ने 9 स्वर्ण पदकों समेत कुल 11 पदक हासिल किए हैं और अभी तो सफर जारी है। करीब 124 साल पहले ब्रिटिश मूल के भारतीय खिलाड़ी नॉर्मन प्रिचार्ड ने 1900 के ओलंपिक में 200 मीटर फर्राटा और 200 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक जीते थे, लेकिन भारत तब गुलाम देश था। मनु और सरबजोत दोनों ही हरियाणा के खिलाड़ी हैं। वे 2019 से मिश्रित निशानेबाजी का साथ-साथ अभ्यास करते रहे हैं, बल्कि राष्ट्रीय और विश्व कप तथा अन्य मुकाबलों में स्वर्ण पदक जीतते रहे हैं। यह सरबजोत ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया, जब उन्होंने इस उपलब्धि की बधाई देने के लिए फोन किया था और मिश्रित टीम के बारे जिज्ञासा प्रकट की थी। सरबजोत ने प्रधानमंत्री के जरिए देश को आश्वस्त किया कि अगली बार वे स्वर्ण पदक जीत कर दिखाएंगे। बेशक यह उनके संघर्ष, जुनून, लक्ष्य, अनथक मेहनत का ही नतीजा है कि दोनों ओलंपिक पदकवीर हैं।

यह वाकई असामान्य और अविश्वसनीय उपलब्धि है। हरियाणा तो क्या, देश भर में निशानेबाजी कोई पारंपरिक खेल नहीं है। हरियाणा कुश्ती, कबड्डी, मुक्केबाजी के लिए विख्यात राज्य है, लेकिन निशानेबाजी ने उसे नए मुकुट पहना दिए हैं।

राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 2004 के एथेंस ओलंपिक में निशानेबाजी का रजत पदक जीता था। अभिनव बिंद्रा 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इसी खेल की भिन्न शैली के चैम्पियन बने। वहीं निशानेबाजी का एकमात्र ओलंपिक स्वर्ण पदक भारत के हिस्से आया था। निशानेबाजी में रजत पदक विजेता विजय कुमार और कांस्य पदकवीर गगन नारंग सरीखे नाम भी अविस्मरणीय हैं, लेकिन दोहरे पदक की सफलता मनु ने ही हासिल की है और बेटी ने इतिहास का नया शिलालेख लिख दिया है। भारत में अब खेल पेशेवर हो गए हैं। अब बड़ी-बड़ी कंपनियां खेलों को प्रायोजित करती हैं और पदकवीर खिलाडियों को नौकरी भी देती हैं। क्रिकेट के आईपीएल मुकाबले पेशेवर खेल के ज्वलंत उदाहरण हैं। 18-20 साल का युवा भी करोड़पति हो सकता है। यह परंपरा वहां से शुरू हुई, जब 1983 में तत्कालीन विश्व चैम्पियन टीम को पराजित कर भारत की टीम विश्व चैम्पियन बनी थी। कप्तान कपिल देव ने ट्रॉफी का वह सम्मान पूरी दुनिया के सामने हासिल किया था।

दरअसल वहीं से भारत में खेल के प्रति मानसिकता बदली और आज खिलाडियों की प्रतिष्ठा भी है और एक सफल करियर भी है।

मनु की उम्र भी अभी 22 साल है और वह करोड़पति है। वह अपने खेल की विश्व चैम्पियन मानी जाती है। खेल के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की निजी दिलचस्पी भी है। वह खिलाडियों से लगातार संवाद करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते रहते हैं, मुलाकातें करते रहते हैं। उन्होंने देश के कोने-कोने से खेल प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें तराशने वाले अकेले 'खेलो इंडिया कार्यक्रम' के लिए 900 करोड़ रुपए बजट में आवंटित कराए हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए और उस पर लगातार चिंतन-मनन करना चाहिए कि भारतीय खेल की विश्वस्तरीय मंजिल अभी मीलों दूर है। मनु-सरबजोत सरीखी दुर्लभ चांदनियां हैं, जो हमारे खेल को रोशन करती हैं। अभी कई और रोशनियां चमकेंगी। उन्हें भी शाबाश देते रहिए। एक भारतीय शटलर ने भी अपना मुकाबला जीत लिया है। इसलिए पेरिस ओलंपिक में अभी हमारी उम्मीदें कायम हैं। शूटिंग में भी एक और मुकाबला होना है, शायद एक और पदक इसमें भी आ जाए।

श्रावण अष्टमी मेले के लिए रंग-बिरंगे फूलों से सजने लगे प्रदेश के शक्तिपीठ

पांच से 14 अगस्त तक होगा नवरात्र मेलों का आयोजन; मइया को लगेंगे विशेष भोग, मंदिरों के खुलने का समय तय

अमन वर्मा — शिमला

प्रदेश के पांच शक्तिपीठों में पांच से 14 अगस्त तक श्रावण अष्टमी मेले का आयोजन किया जाएगा। सावन अष्टमी नवरात्र मेले के लिए मइया के मंदिर रंग-बिरंगे फूलों से सजने शुरू हो गए हैं। सावन अष्टमी मेलों के दौरान प्रदेश के पांच शक्तिपीठों में मइया की विशेष पूजा-अर्चना व मइया को विशेष व्यंजनों के भोग लगाए जाएंगे। प्रदेश के पांचों शक्तिपीठों में श्रीबज़्रेश्वरी देवी, श्रीज्वालामुखी, श्रीनयनादेवी, श्रीचामुंडा देवी व श्रीछिन्नमस्तिका धाम चिंतपूर्णी में मइया के स्नान, शृंगार व आरती अलग-अलग समय तय किया गया है। चिंतपूर्णी मंदिर के बिरादरी सभा के प्रधान रविंद्र छिंदा ने बताया कि नवरात्र में मां के दर्शनों के लिए मंदिर 24 घंटे खुला रहेगा। रात 11 से 12 बजे तक केवल सफाई के लिए मंदिर बंद किया जाएगा। सुबह चार बजे मइयों के स्नान के बाद शृंगार किया जाएगा और मां को आरती के साथ भोग लगाया जाएगा। वहीं नयनादेवी मंदिर नवरात्र में रात 12 से दो बजे तक बंद किया जाएगा। मंदिर पुजारी तरुणेश शर्मा ने बताया कि इन दो घंटों में मइया का स्नान और शृंगार के बाद मइया की एक साथ चार आरतियां की जाएंगी। मंदिर में दोपहर 12 से साढ़े 12 बजे और शाम को मइया को विशेष भोग लगाए जाएंगे। ज्वालाजी मंदिर सुबह चार बजे खुलेगा और रात 10 बजे बंद होगा। मंदिर के पुजारी अनिल शर्मा ने बताया कि नवरात्र में ज्वाला मां की सुबह चार बजे स्नान व शृंगार के बाद आरती होगी, जिसमें मइया को भोग लगेंगे। दोपहर साढ़े 12 से साढ़े 12 बजे तक मइया को आरती के साथ कांगड़ी धाम का भोग लगेगा।

पुजारी अनिल शर्मा ने बताया कि सप्तमीं, अष्टमी और नवमीं के दिन सारी रात मंदिर मइया के दर्शनों के लिए खुला रहेगा। वहीं चामुंडा देवी मंदिर में नवरात्र के दौरान मां को विशेष भोग लगाए जाएंगे। मंदिर के पुजारी ओम व्यास ने बताया कि सावन अष्टमी नवरात्र में मंदिर सुबह पांच बजे खुलेगा और रात 10 बजे तक बंद होगा। उन्होंने बताया कि सुबह मां को हलवा और चने का भोग लगेगा, उसके बाद दोपहर 12 बजे मां को दाल, चावल, सब्जी का भोग लगेगा। शाम को चार बजे मइया के स्नान के बाद शृंगार और सायं सवा आठ बजे मइया की आरती होगी। ब्रजेश्वरीदेवी मंदिर नवरात्र के दौरान सुबह चार से रात नौ बजे तक खुला रहेगा। मंदिर के पुजारी राम प्रसाद ने बताया कि सुबह पांच बजे में मइया का स्नान, शृंगार व आरती के साथ चना-पूरी, मेवे व दूध का भोग मां को लगाया जाएगा। इसके बाद दोपहर 12 बजे चावल, दाल और सब्जी का भोग लगेगा। उन्होंने बताया कि शाम को साढ़े सात बजे मइया को आरती के साथ चना पूरी भोग लगेगा, उसके बाद रात नौ बजे मां को मेवा और दूध-फलों का भोग लगाया जाएगा।

माता श्रीबज्रेश्वरी | माता श्रीचिंतपूर्णी | माता श्रीनयनादेवी | माता श्रीचामुंडादेवी | माता श्रीज्वालामुखी

अदब की महफिल : संजय एम.तराणेकर की नजर से

खूबसूरत शायरी का आगाज़ करती शाम

लगभग डेढ़ घंटा देरी से प्रारम्भ हुई ₹अदब की महफ़लि₹ का साढ़े 6 बजे आगाज़ हुआ. अक्सर ऐसी महफिलों में नए नवेले शायरों को अवसर देकर नवाज़ा जाता हैं. उसका सबसे बड़ा कारण मुशायरा सुनने आए श्रोतागण आख़री तक अपनी कुर्सीयों पर बैठे रहें. इस महफ़लि के साक्षी रहें ज़नाब संजय एम.तराणेकर ने बताया सर्वप्रथम माइक सँभालते ही पारसजी ने पेड़ लगाने और पानी की उपलब्धता व वाटर लेवल नीचे जाने को लेकर जागरूकता पर प्रकाश डाला. चूकि अदब की महफ़लि का संचालक मंडल ही लम्बा-चौड़ा हैं तो हेमंत गट्टानी जी ने स्वागत सम्मान की कमान अपने हाथों रखी. अंत में वे थोड़ा नाराज़ भी हुए. वे भी शेरों शायरी करते रहें.

महफ़लि की शुरुआत की मुंबई से पधारे अश्विन मित्तल ने की. वे बड़े जोश में सुनाते हैं - "सारे इक्के खड़े हैं शर्मिंदा बाजी जीती गई है जोकर से जो कुल्हाड़ी का साथ देती हो उसको लकड़ी नहीं समझता मैं लेनदार आ गए हैं घर के अंदर तक पैर बाहर हो गए थे मेरे चादर सेर₹ वे अंत में कहते है - ₹ज़बान और करम दोनों का धनी हूँ मैं, ज़बान और करम दोनों का धनी हूँ मैं, कि उर्दू बोलने वाला सनातनी हूँ मैं...₹ इस तरह उन्होंने आते ही दिल जीत लिया और ऐसे कलाम पेश किए कि लोगों ने खड़े होकर उनका इस्तक़बाल किया और खूब तालियां बजाई।

लुधियाना के मुकेश आलम ने भी समां बाँधने का इज़हार किया. ₹रात ठहाके मार रही थी, अंधेरे को साथ लिए इतने में एक जुगनू निकला, तेरी ऐसी तैसी रात,अफवाहों को उड़ने की आजादी है सच को रुकते-रुकते जाना पड़ता है."

आगे तीसरा नंबर था गाजियाबाद आई इकरा अंबर का जो मूल रूप से इंदौर की रह चुकी हैं. वे फरमाती हैं -

- जान बन के तुम्हें राम पुकारा है बहुत मैंने वनवास में भी हिज्र गुजारा है बहुत जिस तरह शर्त वह लगाता है जिंदगी अपनी हार बैठेगा.₹

यहाँ तक आते आते श्रोताओं की वाहवाही और फरमाइशों का दौर चल चुका था. जिससे इस बात का भी पता चला की शायरों से वे वाकिफ़ हैं. सुंदर मालेगांवी ने स्वयं के काले होने पर भी शायरी की. असल में उन्होंने शायरी कम वरन स्टैंडअप कॉमेडियन का ज़बरदस्त रोल अदा किया। उनकी खासियत ये रही कि उन्होंने लतीफे, राग, जुमले और गीतों से महफिल अपने नाम कर लीं. जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। इसके बाद युवा शायर जुबैर अली कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नज़ीर पेश कि - ₹अपने क़तरों से मुझे मुकद्दस कर दो, गंगा की तरह छूकर बनारस कर दो.₹

अब आगे बारी थी अबूधाबी (संयुक्त अरब अमीरात) से आए मुख्य शायर सैयद सरोश आसिफ की। अदबी की मिठास लिए उनके शेर बड़ी संजीदगी से सुने गए- ₹मैं खुद अपनी गजलें अक्सर पढ़ता हूं. हैरानी से कैसे-कैसे शेर पढ़ देता हूं आसानी से शेर में वह तस्वीर बनाई जा सकती है जो अंधों को भी दिखलाई जा सकती है. बातों बातों में अम्मी ने फिर पूछा है बेटा क्या छुट्टी बढ़वाई जा सकती है.₹

इसके बाद ग्वालियर के मदन मोहन दानिश ज़ब सुनाने लगे तो वंस मोर की आवाज़े गूंजने लगी। हालांकि वे एक ही लाइन को तीन बार रिपीट करते रहें. बावजूद इसके श्रोता दाद देते गए. दानिश साहब फरमाते हैं - ₹हमें पता है कि मसरूफ हो बहुत फिर भी हमारी दस्तकें सुनते रहो जमीर हैं हम खामोशी को मेरी दुआ समझो और जो बोल दूं हुआ समझो.₹

अब बारी थी निजामत कर रहे अमरावती से आए अबरार काशिफ की. इनका फोकस इश्क पर था. इनकी खूबी ये रहीं की एक ही सांस में एक बड़ी नज़्म पढ़ दी. जिसे खूब दाद मिली. इनकी आवाज़ में वो जादूगरी नज़र आई की हर कोई इनका प्रशंसक बना गया. वे कहते हैं -₹हवस को दूर रखो इश्क की निगाहों से इस शराब में पानी नहीं मिलाते हैं आंखों के पैमाने छलके होते है.₹

महफ़लि की अंतिम कड़ी में नोएडा के नौमान शौक की ख़ासियत संजीदा और गहरे शेर कहने की रहीं है। उन्होंने अपनी शायरी को एक जर्क करार दिया, जिसे बर्दाश्त करने की गुजारिश करते हुए भरपूर शेर सुनाए।

₹मैंने सामने सफर बांध के फिर जमीर जाग रहा हो तो नींद क्या आए यह शोर वह सुने जिसको सुनाई दे."

इंदौर के लाभ मंडपम में शहर की संस्था 'अदब की महफिल' की 11वीं सालगिरह पर हुए इस मुशायरे को लोग लंबे अर्से तक याद रखेंगे। 9 शायरों ने बरबस ही जो समां बांधना प्रारम्भ किया तो श्रोतागण गोते लगाते चले गए. इस पर समीक्षा करने बैठे संजय एम. तराणेकर ने अर्ज़ किया हैं -

₹वक़्त तुम ख़ुद को भी दिया करों,
यारों ऐसी महफ़लिं सज़ती हैं कम
कभी अदब की महफ़लि में आकर,
जुबा के ज़ाम थोड़े-थोड़े पिया करों."

संजय एम.तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
98260-25986

राव आईएएस कोचिंग सैंटर ने मृतक स्टूडेंट्स के परिजनों को 50 लाख देने का किया ऐलान,लगाई शर्त

परिवहन विशेष न्यूज

परिवहन विशेष।एसडी सेठी। राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेन्द्र नगर स्थित राव आईएएस कोचिंग सैंटर ने हादसे के पांच दिन बीत जाने के बाद सामने आए उनके वकील मोहित सराफ ने मृतको के परिवार को 50लाख रूपये देने का ऐलान किया है। इस बावत वकील मोहित सराफ ने कहा कि तीनों मृत स्टूडेंट्स के परिजनों को अभी 25 लाख दिए जाएगे।और बाकी के 25 लाख रूपये अगले 6 महीने के अंदर जब भी कोचिंग इंस्टिट्यूट के सीईओ अभिषेक के जेल से बाहर आने के बाद दिए जाएगे।

वकील अभिषेक ने कहा कि हम अभिषेक के जेल से बाहर आने के बाद ही शेष पैसों की व्यवस्था कर पाएगें। वकील अभिषेक ने मीडिया में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वो पीडित परिवारों के दुख को समझ सकते है। जिन्होंने अपने बच्चे खोए है। उन्होने कोचिंग सीईओ और उनके परिवार का पक्ष रखते हुए कहा कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन की वजह से कई चीजे रूक सी गई है। वो चाहते है कि छात्र अपना विरोध प्रदर्शन खत्म करे।और चीजें पटरी पर आ जाए। संस्थान के स्टाफ की सैलरी भी नही दी गई है। गौरतलब है कि बीते शनिवार को दिल्ली के राजेन्द्र नगर इलाके में बडा हादसा सामने आया था।इस हादसे में डूबने से तीन छात्रों की मौत हो गई थी। इसके बाद छात्रों समेत अन्य राजनीतिक दलों ने भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। इसके बाद कई कोचिंग सैंट्रो को सील कर दिया गया। छात्रो का विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है।

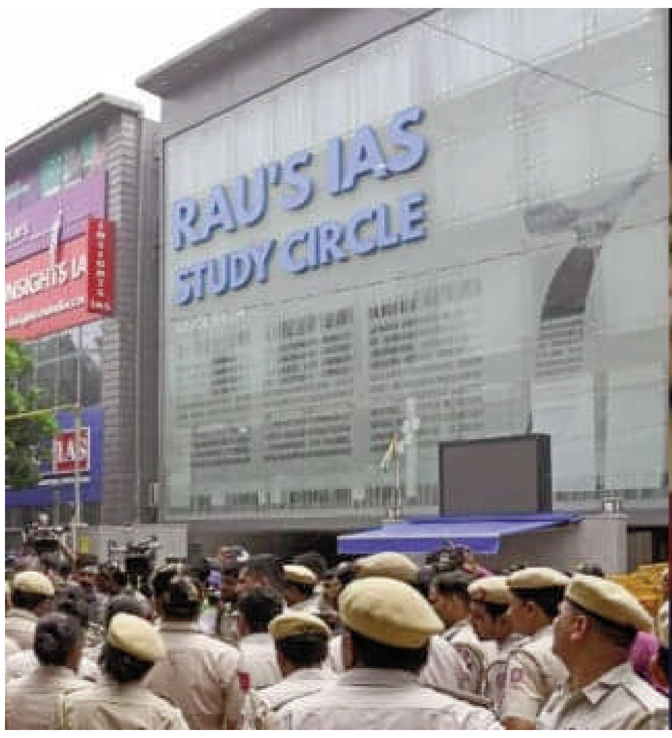

संगीत के बिना जीवन अधूरा है -डॉ. राजेंद्र जैना

सुषमा रानी, संगीत के बिना हम जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस सृष्टि का उत्थान ही "ओम" से हुआ है ,जिसे हिंदू धर्म में सृष्टि की आदि ध्वनि माना जाता है। संगीत, भावनाओं का संक्षिप्त रूप है और इसी संगीत को अपनी आवाज़ के जरिये हर इंसान की आत्मा तक पहुंचाया मोहम्मद रफ़ी साहब ने, रफ़ी जैसे कलाकार मरा नहीं करते अमर होते है यह कहना था प्रसिद्ध व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और कला प्रमोटर डॉ. राजेंद्र जैना का, जिन्होंने रफ़ी साहब की 45वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एएएफटी स्कूल ऑफ़ म्यूज़िक व जे. आर. एंटरटेनमेंट द्वारा आयोजित एक संगीत कार्यक्रम का मुख्य अतिथि के रुप में उद्घाटन किया। इस अवसर पर मारवाह स्टूडियो के अध्यक्ष संदीप मारवाह मौजूद रहे, संदीप मारवाह ने कहा की जो भी इंसान संगीत को चाहता है वो रफ़ी साहब को नही चाहता हो ऐसा हो नहीं सकता, जो रफ़ी साहेब को सुनता हों वो संगीत से अलग हो ऐसा हो नहीं सकता। इस अवसर पर डॉ. राजेंद्र जैना ने संगीत उद्योग में मोहम्मद रफ़ी के स्मरणीय योगदान के विषय में बात की, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान की,सभी भाषाओं में 7000 से अधिक गीतों की रचना पर प्रकाश डाला । यहां तक की अंग्रेजी भाषा नही जानते हुई भी अंग्रेजी में अपनी आवाज़ के जादू का परचम लहराया । रफ़ी साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए, डॉ जैना ने रफ़ी जी के शम्मी कपूर पर फिल्माए गए, कई गाने भी गाए, मारवाह स्टूडियो में छात्रों से भरा खचाखच सभागार जोरदार तालियों से गूंज रहा था। यह कार्यक्रम न केवल मोहम्मद रफी की संगीत प्रतिभा का जश्न मनाने का अवसर था, बल्कि उन छात्रों को सम्मानित करने का भी अवसर था, जो उनकी विरासत को जीवित रखना चाहते हैं। संदीप मारवाह ने डॉ. राजेंद्र जैना को एएएफटी के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविजन क्लब की आजीवन सदस्यता प्रदान करते हुए सम्मानित भी किया।

रोहिणी,अवंतिका,स्थित आशा किरण होम में 1 महीने में 13 बच्चों की मौत,आतिशी ने दिए जांच के आदेश

परिवहन विशेष।एसडी सेठी।

दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग के तहत रोहिणी,अवंतिका स्थित आशा किरण बैगर होम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इस शेल्टर होम में पूरी दिल्ली से पकडे गए लावारिस मानसिक ,मंदबुद्धि , दिव्यांगों समेत बुजुर्गो को रखा जाता है। इस आशा किरण होम पर लापरवाही, और बेकद्री के आरोप अक्सर लगते रहते हैं।

लापरवाही का ये आलम है कि इसमें 500 की जगह 950 आश्रितों को भेड बकरियों की तरह ठूंसा गया है। यहां पुलिस द्वारा पकड कर लाए गए मंदबुद्धि, या मानसिक रोगियों के साथ अत्याचार किया जाता है। वह गंदगी के माहोल में बिमारी से घिरे पडे रहते है, उनकी ओर वहां तैनात स्टाफ,केयर टेकर अपनी सिर्फ ड्यूटी बजाकर टाइम पास करते है।उन्हें वक्त पर दवाई नहीं दी.जाती है। जिससे 25 के करीब तो ,TB के पेशेंट बन गए है। दो-तीन साल पहले आरटीआई एक्टिविस्ट राजवीर बंसल ने यहां हुई मोतो का मीडिया में खुलासा कर हडकंप मचा दिया था। उन्होने आरटीआई के तहत आशा किरण होम के अंदर की जानकारी से यहां की खस्ता हालत में बंद मंदबुदियों के शोषण और मौतों की जानकारी को मीडिया के आगे खुलासा किया था।अब एक बार फिर मौत का सिलसिला जारी है। आशा किरण होम में एक महीने में 13 मौते होने से हडकंप मच गया है। आनन फानन में समाज कल्याण मंत्री आतिशी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए है। बता दें कि राजधानी दिल्ली में मंदबुद्धि बच्चों के लिए बनाया गया आशा किरण होम अब यहां की स्थित के मद्देनजर डेथ चेंबर बन गया है। यहां पर लडके,लडकी, बुजुर्ग, बच्चे तक बंद है। इनकी हालत की सुध लेने वाला कोई नही है। जब कोई बडा हादसा हो जाता है तो तमाम अधिकारी, नेता ,मंत्री का जमावड़ा हो जाता है। और हर बार के हादसे के बाद जांच बैठा दी जाती है,जिसकी रिपोर्ट को सामने तक नहीं लाया जाता है।और ना ही इसके.जिम्मेवार अधिकारी, कर्मचारियों के खिलाफ ही कार्यवाई की जाती है। हालत ये है कि जेल की शक्ल में बनी इस सरकारी बिल्डिंग से बाहर के किसी शख्स को ये तक भान नहीं है कि इसके अंदर क्या होता है? यहां के आसपास अवंतिका में रहने वाले लोग इसे पागलपनखाना बताते है। बल्कि इसके सामने वाली सडक को वह पागलखाने वाली रोड के नाम से पुकारते है। लोगों को सिर्फ इतनी भर जानकारी है। बता दें कि जुलाई महीने में ही 20 दिन के अंदर 14 बच्चों की मौत हुई है।यहां साल दर साल मौते हुई है। जिनमें जनवरी में-3, फरवरी में-2, मार्च में-3, अप्रैल में-2, मई में-1,जून में-3, और जुलाई में 13 मौते हुई है। गौरतलब है कि इस बावत होम प्रशासन इतने गंभीर विषय पर मुंह पर उंगली रखे बैठा है। वहीं रोहिणी एसडीएम से मिली जानकारी के मुताबिक अवंतिका के आशा किरण होम में मौतों की बात सही है। उल्लेखनीय है कि रोहिणी के सैक्टर-1,अवंतिका स्थित आशा किरण होम में मंद बुद्धि बच्चों समेत बुजुर्गो को रखा जाता है। अक्सर इस पर आरोप लगते रहते हैं कि यहां कैद लोगो की देखरेख ठीक से नहीं करते है। इसी वजह से पिछले कुछ वर्षो में रहस्यमय ढंग से यहां होने वाली मौते कई सवाल खडे करती है। यहां हुई मौतो की किसी को हवा तक नहीं लगती।सूत्रो से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार द्वारा संचालित इस आशा किरण होम में मानसिक रूप से बिमार लोगों की देखरेख ठीक से नहीं की जाती है। अक्सर आशा किरण होम में एंबुलेंस का आना जाना लगा रहता है। लेकिन प्रशासन हमेशा मौत के रहस्य को छिपाता रहा है।बता दे कि इससे पहले भी कई मौते हुई है। यहां 10 तक की मौत हुई थी। लेकिन इस बार मामला एक महीने के भीतर 14 मौतों का है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना मिलने का हवाला देकर अपना पिंड छुडाया जा रहा है। लेकिन रोहिणी एसडीएम का मानना है कि मौत की वजह खराब पानी हो सकता है। बहरहाल नाम न छापने की शर्त पर एक समाजिक कार्यकर्ता के मुताबिक बच्चो को जो पहले सुविधा मिलती थी,अब वह सुविधा नहीं मिलती है। अंदर के बहुत बुरे हाल है।ना बच्चों को पूरी डाइट मिलती है, 4 साल पहले तक बच्चों को दूध,अंडा,सब मिलता था, अब सब बंद हो गया। सिर्फ दाल-रोटी मिलती है। इस वक्त अंदर कम से कम 20 से 25 बच्चों को TB की बिमारी है। एसडीएम मनीष वर्मा के मुताबिक जैसे ही इसकी खबर आई तो हमने तुरंत तहकीकात शुरू की। जो जानकारी आई वह बिल्कुल सत्य है। मृत्यु दर पहले के मुकाबले ज्यादा है। यहां की देखरेख करने वाले डिप्टी डायरेक्टर ने भी स्वीकार किया कि मौत की संख्या ज्यादा है। अभी बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद वजह का खुलासा होगा। बहरहाल प्रशासन को पानी की जांच समेत वाटर फिल्टर बदलवाने के निर्देश दिए है। आशा किरण होम में मौतों को लेकर महिला आयोग भी एक्टिव हो गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी आशा किरण होम में हुई मौतो को लेकर कहा कि हम फेक्ट फाइंडिंग टीम को स्पॉट पर भेज रहे है।टीम मानसिक स्वास्थ्य रोगियों की मौत के लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों से मुलाकात करेगी।वे कौन लोग है,जिन्हें इन आश्रय स्थलों को चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। इस बीच पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी सामने आ गए हैं। उन्होने कहा कि भाजपा प्रदर्शन करने पहुंच रही है।क्योंकि उन्हें पता है कि आशा किरण होम दिल्ली सरकार के सोशल वेल्फयर विभाग के अंडर आता.है। गोपाल राय ने कहा कि बहरहाल हम क्लोजली

एलजी साहब ने कई बार जनता के हक की आवाज सुनी है- दिलीप पांडे

सुषमा रानी

नई दिल्ली, दिल्ली के मयूर विहार फेस तीन में डीडीए के खुले नाले में गिर कर हुई मां-बेटे की दुखद मौत को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक एवं डीडीए के सदस्य दिलीप पांडे ने एलजी को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और पीड़ति परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस घटना को दो दिन होने वाले हैं, लेकिन अभी तक किसी जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने एलजी साहब के सामने जनता के हितों को उठाया और उन्होंने हमारी बात सुनी है। इस मामले में भी हमें भरोसा है कि वो सख्त कार्रवाई करके कड़ा संदेश देंगे ताकि भविष्य में दोबारा ऐसी घटना न हो।

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक दिलीप पांडे ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि 31 जुलाई की रात को दिल्ली के कोंडली विधानसभा में हुए दुखद हादसे में दो निर्दोष जानें चली गईं। हम बार-बार कहते आ रहे हैं कि भाजपा दिल्लीवालों से नफरत करती है। उसकी नजर में दिल्लीवालों की जान की कोई कीमत नहीं है। दिल्ली के बॉर्डर इलाके में जिस नाले का पुनर्निमाण का कार्य चल रहा था, वहां डीडीए के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से एक महिला और उसके ढाई साल के बच्चे की जान चली गई। उस मासूम बच्चे को अभी दुनिया में बहुत कुछ देखना था, अपने परिवार के सपने पूरे करने थे। लेकिन इससे पहले कि वो बच्चा बड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा हो पाता, डीडीए के नाले ने उसकी जान ले ली। यह घटना बहुत आहत करने वाली है।

उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से मैं भी उस डीडीए में कम हैसियत रखने वाला मामूली सा सदस्य हूं। लेकिन दिल्ली का एक नागरिक और डीडीए का सदस्य होने के नाते मैंने डीडीए के अध्यक्ष एलजी साहब को एक पत्र लिखा है। एलजी साहब ही डीडीए चलाते हैं। ऐसे कई मौके आए जब हमने जनता के हक के लिए एलजी साहब के सामने बात रखी और उन्होंने इसे सुना। यह चिट्ठी भी उन तक जरूर पहुंचेगी। मुझे उम्मीद है कि इस घटना के लिए जो भी लापरवाह अधिकारी शामिल हैं, एलजी साहब हक और इंसाफ की आवाज बनते हुए उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक कड़ा संदेश देंगे, ताकि आगे डीडीए की ऐसी लापरवाही से कभी भी किसी और बेगुनाह को अपनी जान न गंवानी पड़े।

उन्होंने एलजी को चिट्ठी लिखने की वजह बताते हुए कहा कि इस घटना को बीते अब 36 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन मेरी जानकारी में अभी तक किसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। अगले हफ्ते डीडीए की बोर्ड मीटिंग है। हमें उम्मीद है कि इस बैठक में एलजी साहब न सिर्फ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बल्कि पीड़ति परिवार को मुआवजा भी दिलवाएंगे ताकि इस घटना के बाद अपनी आगे की जिंदगी बिताने के लिए उनकी थोड़ी आर्थिक मदद हो सके। इन सारी बातों को मैंने इस पत्र में लिख दिया है। आज यह उन तक पहुंच जाएगा। मैं बड़ी उम्मीद और भरोसे के साथ यह चिट्ठी लिख रहा हूं कि एलजी साहब इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे।

जब से "आप" दिल्ली की सत्ता में है, तब से केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को कमजोर करने का प्रयास कर रही है- गोपाल राय

सुषमा रानी

नई दिल्ली। मयूर विहार फेस-3 में डीडीए के खुले नाले में गिरने से हुई मां-बेटे की दुखद मौत पर भाजपा, एलजी और प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़ा किया है। ''आप'' ने एलजी को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए शनिवार को राजनिवास पर विशाल विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। ''आप'' के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने यह जानकारी देते हुए कहा कि डीडीए की लापरवाही से मां-बेटे की मौत हुई है, लेकिन राजेंद्र नगर की दुखद घटना पर राजनीति करने वाली भाजपा और एलजी इस मामले पर चुप हैं। एलजी साहब ने घटना के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की है और न तो पीड़ति परिवार को मुआवजे की घोषणा की है। वहीं, भाजपा अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के चक्कर में इतने नीचे गिर चुकी है कि उसके कुछ नेता मयूर विहार की घटना की वीडियो बनाकर चिल्लाने लगे कि ये दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी का नाला है। लेकिन जब उनको पता चला कि नाला तो डीडीए का है, उन्हें सांप सुंघ गया।

आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय और कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली की जनता ने प्रचंड बहुमत देकर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। जब से दिल्ली में हमारी पार्टी की सरकार बनी है, तब से केंद्र की भाजपा सरकार ने दिल्ली सरकार को कमजोर करने का अभियान चला रखा है। दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए राज्य और केंद्र सरकार का कार्यक्षेत्र पहले से ही बंटा हुआ है। यहां डीडीए, पुलिस, और जमीन केंद्र सरकार के तहत आते हैं। लेकिन भाजपा ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास जो अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग और

तमाम कार्यों को संचालित करने व निर्णय लेने का अधिकार था, उसे भी सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच के फैसले के खिलाफ जाकर पलट दिया। उन्होंने संसद में कानून पास करके दिल्ली सरकार के अधिकारों को भी छीन लिया। भाजपा ने लगातार अरविंद केजरीवाल द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिलाओं की यात्रा और बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के लिए किए गए कार्यों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की।

गोपाल राय ने कहा कि इस नए कानून के माध्यम से भाजपा ने एलजी की आड़ में केजरीवाल सरकार को निष्क्रिय करने की साजिश रची। लेकिन इनके सारे षड़यंत्रों के बावजूद दिल्ली सरकार का काम चलता रहा। इसके बाद इन्होंने पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर लिया, और फिर बिना किसी सबूत के फर्जी केस बनाकर सीएम को गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल को ईडी कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी सीबीआई का इस्तेमाल करके उन्हें जेल में डाल दिया। इन सबके बावजूद दिल्ली सरकार अपना काम कर रही है और दिल्ली के लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। लेकिन भाजपा सारे अधिकार छीनने के बावजूद दिल्ली सरकार के लगातार हो रहे काम को देखकर आज भी परेशान है। तमाम साजिश करने और मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के बाद भाजपा आज भी बैचेन है।

गोपाल राय ने बताया कि इस घटना के बाद भाजपा के नेता और बड़े प्रवक्ता मौके पर वीडियो बनाने पहुंचे थे, जिसमें वो चिल्ला-चिल्ला कर बता रहे थे कि ये दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी का नाला है। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि ये डीडीए का नाला है। इसके बाद उन्हें सांप सुंघ गया। अब इसपर कोई बोलने को तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के चक्कर में भाजपा और कितना नीचे गिरेगी? पहले ये केजरीवाल को बदनाम करने के लिए नाले का वीडियो बनाने चले गए, लेकिन जब बाद में पता चला कि वह तो दिल्ली सरकार का नहीं केंद्र सरकार के तहत आता है, तो इसपर बोलने के लिए भाजपा का एक भी नेता तैयार नहीं है। क्या उस मां-बच्चे की मौत, मौत नहीं है?

गोपाल राय ने कहा कि भाजपा के सुबह से शाम तक केजरीवाल को गाली देने से दिल्लीवालों की समस्या का हल नहीं होगा। भाजपा चाहती है कि उसके पास सारी ताकत रहे, लेकिन उसे कोई काम न करना पड़े। 15 साल तक एमसीडी में रहने के बावजूद इन्होंने एक काम नहीं किया। तीन बार से लगातार भाजपा के सांसद जीत रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं करते हैं। और केंद्र में इनकी सरकार दिल्ली के लिए बजट नहीं देती। ये लोग काम में जीरो और पावर में हीरो बनना चाहते हैं। भाजपा को अपनी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी। इनके सांसदों से जब काम का हिसाब मांगा जाता है, तो भागने लगते हैं। जब भी भाजपा की जिम्मेदारी का सवाल आता है, तो भागने लगती है। लेकिन जैसे ही केजरीवाल की बात होती है, उसके पास सारी ताकत आ जाती है। फिर एक के बाद एक प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। फिर एलजी भी चिट्ठी लिखने लगते हैं, भाजपा के मंत्री, सांसद भी जाग जाते हैं। भाजपा की यह दोहरी रणनीति दिल्ली में नहीं चलेगी। जिस तरह से दिल्ली सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने काम को आगे बढ़ाया है, भाजपा के सांसदों, केंद्र सरकार और एलजी को भी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं, तो हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए भाजपा को चुप्पी नहीं साधने देंगे।

कुलदीप कुमार नेकहा कि डीडीए के उन अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने गुरुवार को भी इस मांग को लेकर प्रदर्शन किया था ताकि उस मां-बेटे को न्याय मिले। एलजी तत्काल प्रभाव से उन अधिकारियों को निलंबित करके उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज करें। क्योंकि वह हादसा नहीं हत्या थी। अगर वह नाला ढका हुआ होता, तो उनकी जान बच सकती थी। एलजी साहब इससे बच नहीं सकते हैं। उन्हें दिल्ली सरकार के कामों का क्रेडिट लेने का बहुत शौक है। डीजेबी, पीडब्ल्यूडी जैसे कई विभागों के काम में वह अड़चन पैदा करते हैं। लेकिन जो विभाग उनके अधीन हैं, कम से कम उन्हें तो वह अच्छे से संभालें। अगर उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, तो भविष्य में इस तरह के हादसे रुकेंगे। अधिकारियों में खौफ आएगा कि अगर वे दिल्लीवालों की जान से खिलवाड़ करेंगे तो उनकी नौकरी जा सकती है। लेकिन अगर उन्हें एलजी साहब का संरक्षण मिलेगा, तो वे इसी तरह लापरवाही करेंगे। एलजी साहब ने दिल्ली में जो यह चलन शुरू किया है, उसे खत्म करना होगा।

नोएडावासियों को होगी थोड़ी परेशानी, अब रविवार सुबह तक बंद रहेगा डीएनडी

परिवहन विशेष न्यूज

डीएनडी पर रविवार सुबह तक डायवर्जन रहेगा। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे से डीएनडी होकर आश्रम की ओर जाने वाले वाहन दलित प्रेरणा स्थल से चिल्ला रेड लाइट अक्षरधाम सराय काले खां होकर अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे जबकि रजनीगन्धा अंडरपास सेक्टर 16 से डीएनडी होकर आश्रम की ओर जाने वाले वाहन डीएनडी टोल से यू-टर्न लेकर चिल्ला रेड लाइट अक्षरधाम सराय काले खां होकर चलेंगे।

नोएडा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाए जा रहे छह लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे को दिल्ली महारानी बाग जंक्शन से जोडे जाने के कार्य को रविवार सुबह पांच बजे तक किया जाना प्रस्तावित है। इस कारण इस मार्ग पर डायवर्जन रहेगा।

नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे से डीएनडी होकर आश्रम की ओर जाने वाले वाहन दलित प्रेरणा स्थल से चिल्ला रेड लाइट, अक्षरधाम, सराय काले खां होकर अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे जबकि रजनीगन्धा अंडरपास, सेक्टर 16 से डीएनडी होकर आश्रम की ओर जाने वाले वाहन डीएनडी टोल से यू-टर्न लेकर, चिल्ला रेड लाइट, अक्षरधाम, सराय काले खां होकर चलेंगे। यातायात पुलिस ने असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गो का प्रयोग करने की अपील की है।

पुलिस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

नोएडा ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि डायवर्जन के दौरान यहां रात में इस एक्सप्रेसवे लिंक रोड को दिल्ली में महारानी बाग जंक्शन से जोड़ा जाएगा। नोएडा से डीएनडी होकर किसी भी तरह की दिक्कत होने पर वाहन चालक ट्रैफिक पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 9971009001 शिकायत पर कर सकते हैं।

हरिद्वार गया शिवभक्त गंगा नदी में बह गया, तलाश जारी, अभी तक नहीं लगा सुराग

गंगा में डूबने की सूचना मिलते ही उसके परिवार के लोग बदहवास हो उठे। परिजन युवक की तलाश में हरिद्वार के लिए रवाना हो गए हैं।

परिवहन विशेष न्यूज

हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में परिजनों और दोस्तों के साथ हरिद्वार से कांवड़ लेने सिकंदरपुर गांव निवासी 18 वर्षीय हरीश पाल गंगा में बह गया। सूचना मिलते ही परिवार के लोगों में कोहराम मच गया, जो तुरंत ही हरिद्वार के लिए रवाना हो गए हैं।

सिकंदरपुर निवासी हरीश अपने चाचा और कुछ दोस्तों के साथ गुरुवार को कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार गया था। शाम करीब तीन बजे गंगा स्नान करने के दौरान युवक गंगा के तेज बहाव में बह गया। जिसे देखकर उसके चाचा और अन्य लोगों ने शोर मचा दिया। वहीं स्थानीय पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू कर दी।

ग्राम प्रधान बब्लू यादव ने बताया कि युवक के गंगा में डूबने की सूचना मिलते ही उसके परिवार के लोग बदहवास हो उठे। परिजन युवक की तलाश में हरिद्वार के लिए रवाना हो गए हैं। हरीश का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका है।

कांवड़ियों के एक गुट ने दूसरे गुट पर किया हमला, गाड़ियां तोड़ी; इलाके में तनाव का माहौल

पुलिस के अनुसार सेक्टर-12 प्रेम नगर के दो गुट 27 जुलाई को कांवड़ लेकर हरिद्वार के लिए गए थे। इसमें एक झुग्गी का गुट है और एक सेक्टर 12 में रहने वाले लोगों का। सेक्टर 12 निवासी दीपक ने बताया कि 27 जुलाई को दोनों गुट कांवड़ लाने के लिए हरिद्वार जाने लगे तो झुग्गी वाले गुट ने उनके गुट से तेज संगीत का कांप्टीशन करने की बात कही।

परिवहन विशेष न्यूज

गुरुग्राम। सेक्टर-14 थाना क्षेत्र के सेक्टर 12 प्रेम नगर स्थित मंदिर में जलाभिषेक के बाद कांवड़ियों के एक गुट ने दूसरे गुट पर हमला कर दिया। यह हमला लाठी डंडों, रॉड और तलवारों से किया गया। हमले में दूसरे गुट के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। तोड़फोड़ और पथराव में आधा दर्जन गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। टकराव की सूचना के बाद भारी संख्या में यहां पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है।

पुलिस के अनुसार सेक्टर-12 प्रेम नगर के दो गुट 27 जुलाई को कांवड़ लेकर हरिद्वार के लिए गए थे। इसमें एक झुग्गी का गुट है और एक सेक्टर 12 में रहने वाले लोगों का। सेक्टर 12 निवासी दीपक ने बताया कि 27 जुलाई को दोनों गुट कांवड़ लाने के लिए हरिद्वार जाने लगे तो झुग्गी वाले गुट ने उनके गुट से तेज संगीत का कांप्टीशन करने की बात कही। जब दीपक के गुट ने इसके लिए मना किया तो उन्होंने झगड़ा किया। उस समय विवाद सुलझ गया। आरोप है कि झुग्गी वाले गुट के लोगों ने धमकी दी थी कि कांवड़ लाने के बाद वह उन्हें सबक सिखाएंगे।

सेक्टर 12 के मकान में घुसकर की मारपीट

शुक्रवार सुबह दोनों गुट वापस आए और प्रेम नगर चौक स्थित मंदिर में जलभिषेक किया। सेक्टर 12 निवासी गुट के लोग अपने-अपने घरों में थे। इसी दौरान झुग्गियों में रहने वाले कांवड़ियों के गुट के 15 से ज्यादा लोग हाथ में लाठी-डंडे और तलवार लेकर सेक्टर 12 में बने एक मकान में घुस गए और दूसरे गुट के लोगों से मारपीट की। उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई।

लोगों से मारपीट, गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी रिकार्ड हो गई। इसके बाद आरोपितों ने बाहर खड़ी स्कार्पियो और टाटा 407 गाड़ी को भी पत्थरों व लाठी-डंडों से क्षतिग्रस्त कर दिया।

महिलाओं ने किया प्रदर्शन, रोड जाम करने की कोशिश

टकराव की सूचना के बाद सेक्टर 14 समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को नागरिक अस्पताल भेजा गया। वहीं पीड़ितों से पूछताछ के बाद जब आरोपितों को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो झुग्गी की महिलाओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। यहां की महिलाएं सेक्टर 12 चौक पर आ गईं और जाम लगाने की कोशिश की। पुलिस बल ज्यादा होने से महिलाओं को वहां से हटा दिया गया। फिलहाल यहां भारी संख्या में पुलिसबल को तैनात किया गया है। स्थिति शांतिपूर्ण है।

सेक्टर 12 में जलाभिषेक के बाद कांवड़ियों के दो गुटों में झगड़े की बात सामने आई थी। घायलों को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। एफआइआर दर्ज की गई है। यहां पर स्थिति शांतिपूर्ण बनाने के लिए पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। - करण गोयल, डीसीपी वेस्ट

महाशिवरात्रि पर बुझे दो घरों के चिराग: हाईवे पर हादसे में दो कांवड़ियों की मौत, दोनों दोस्त हरिद्वार से ला रहे थे जल

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (डीएमई) पर शुक्रवार दोपहर को बाइक अनियंत्रित होकर गिरने से दिल्ली के दो कांवडियों की मौत हो गई। दोनों हरिद्वार से जल लेकर दिल्ली की ओर जा रहे थे। हादसे के समय दोनों ने हेलमेट नहीं लगा रखे थे। पुलिस की शुरुआती जांच में हादसे का कारण ओवरस्पीड में बाइक का फिसलना सामने आया है। वहीं, मृतकों की पहचान दिल्ली दिलशाद कॉलोनी के 22 वर्षीय शुभम पांडेय व 24 वर्षीय राहुल दुबे के रूप में हुई। दोनों अविवाहित थे और आपस में दोस्त थे।

गोलचक्कर पर तैनात पुलिसकर्मियों को मिली थी सूचना

सेक्टर 58 थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया सेक्टर 62 गोलचक्कर पर तैनात पुलिसकर्मियों को दोपहर एक बजे एक टेंपो चालक ने सूचना दी कि डीएमई पर कांवड लेकर लौट रहे बाइक सवार दो कांवडिए गिरकर घायल हो गए हैं। तेज रफ्तार बाइक के फिसलने की भी जानकारी दी।

वहीं, मौके पर पहुंची टीम ने दोनों के सिर समेत शरीर के अन्य हिस्से में चोट लगा पाया। राहगीरों की मदद से उन्हें निकट के अस्पताल में भर्ती कराया जहां, चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

जानकारी में सामने आया है कि शुभम और राहुल के साथ अन्य कांवड़िए भी थे। दोनों के तेजी से आगे निकलने के कारण बाकी सभी पीछे छूट गए थे। जिस समय हादसा हुआ हल्की बूंदाबांदी होने के कारण सड़क भीगी थी। फिसलन के कारण बाइक अनियंत्रित हुई हो। हादसे में बाइक भी आगे से क्षतिग्रस्त हो गई।

मौके पर नहीं मिले हेलमेटएन

आईबी चौकी पुलिस ने बताया कि हादसे की स्पष्ट जानकारी करने के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। मौके से दोनों के पास कोई हेलमेट नहीं मिला है। गाजियाबाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन घटना स्थल नोएडा क्षेत्र में होने के कारण लौट गई।

संसद में जाति पर जारी सियासी जंग के राजनीतिक मायने को ऐसे समझिए

कमलेश पांडेय

जातीय या धार्मिक आरक्षण को भी सकारात्मक दृष्टिकोण से देखे जाने की दरकार है, न कि नकारात्मक तौर पर। क्योंकि गुलाम भारत से लेकर आजाद भारत में जाति और धर्म को लेकर जितने भी कानून बनाए गए, वो सब अंतर्विरोधाभाषों से भरे पड़े हैं।

वैदिक या सनातन सभ्यता-संस्कृति में जो 'जाति' कार्यकुशल जनसमूह की कार्यदक्षता की निशानी समझी जाती थी और राष्ट्रीय उत्पादकता में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती आई थी, वही जब लोकतांत्रिक या संवैधानिक सभ्यता-संस्कृति में व्यापक विवाद का वाहक बनकर दिन-प्रतिदिन अनुत्पादक प्रतीत होने लगे, तो देश व समाज के प्रबुद्ध लोगों का चिंतित होना स्वाभाविक है। इसलिए आज संसद में जाति के सवाल पर भाजपा नीत एनडीए और कांग्रेस नीत इंडिया ब्लॉक के बीच जो सियासी जंग छिड़ी हुई है, उसके पीछे के राजनीतिक मायने को समझने और आमलोगों को समझाने की जरूरत है।

पहला, चूंकि राजनीतिक दलों के लिए जाति अब सामाजिक ध्रुवीकरण का औजार और सियासी गोलबंदी का हथियार बन चुकी है, इसलिए उसे सकारात्मक नजरिए से देखे जाने की जरूरत है, न कि नकारात्मक तरीके से। हां, अब जाति के परिप्रेक्ष्य में वह मुद्दा उठाने की जरूरत है, जिससे राजनीतिक दल और उसके 'चतुरसुजान' नेता अब तक बचते आए हैं। जैसे- साधुओं की जाति, वर्णसंकर लोगों की जाति और अंतरधार्मिक विवाह रचाने वाले लोगों और उनकी संततियों के धर्म का मुद्दा आदि सबसे अहम है।

दूसरा, जातीय या धार्मिक आरक्षण को भी सकारात्मक दृष्टिकोण से देखे जाने की दरकार है, न कि नकारात्मक तौर पर। क्योंकि गुलाम भारत से लेकर आजाद भारत में जाति और धर्म को लेकर जितने भी कानून बनाए गए, वो सब अंतर्विरोधाभाषों से भरे पड़े हैं। जिसकी वजह से उनमें स्पष्टता का अभाव तो है ही, लोकतंत्र की मूल भावना स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व भी नदारत है। इस स्थिति के लिए हमारे राजनेता और नौकरशाह दोनों ही जिम्मेदार हैं। लेकिन इस स्थिति को बदलने का साहस किसी भी राजनीतिक दल में नहीं दिखा, जिससे राष्ट्रीय हित और पेशेवर गुणवत्ता गहरे तक प्रभावित होती आई है जिससे वैश्विक मुकाबले में भारत पिछड़ता चला आया।

तीसरा, जाति और धर्म के आधार पर बने कानूनों में व्याप्त विसंगतियों और इससे प्रभावित हो रहे सामान्य जनजीवन के खिलाफ स्वतः संज्ञान न लेकर न्यायविदों ने भी 'कालीदासी विद्वत्ता' का ही परिचय दिया है। जिस देश में वह लोकतांत्रिक न्याय दे रहे हैं, वहीं पर जब कानूनी व न्यायिक प्रावधान व्यक्ति विशेष की स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की पारस्परिक भावना को मुंह चिढ़ाने लगें, तो समझा जा सकता है कि मत समानता रहने के बावजूद पीड़ति व प्रभावित व्यक्ति कितना असहाय महसूस कर रहा होगा। खास बात यह कि इस देश में जाति और जातीय आरक्षण की जो अवधारणा तय की गई है, सवर्ण-पिछड़ा-दलित-आदिवासी और उनकी गरीबी के अलावा अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक के जो मानदंड तय किये गए हैं, वो तार्किक कम, प्रतिशोधी ज्यादा प्रतीत होते हैं। लेकिन क्या मजाल कि कोई इन्हें गलत ठहरा दे या उनमें संशोधन की बात करे। इससे तो यही लगता है कि संविधान निर्माताओं से लेकर संविधान के कथित संरक्षकों और संसद में पिछले लगभग 8 दशक से बैठ रहे अधिकांश माननीयों ने जनतांत्रिक कुएं में पड़ी भांग पी ली है, जिन्हें तर्क और तथ्य से कोई वास्ता नहीं, बस पददलित जनमानस पर निरंतर बिहंसते जा रहे हैं!

चतुर्थ, कुछ यही हाल राष्ट्र में जनमत निर्धारण करने में अमूल्य सहयोग देने वाली समग्र मीडिया इकाइयों और उसके अदूरदर्शी सम्पादकों का भी है, जिन्होंने वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता की बजाय पक्षधरता भरी रिपोर्टिंग की और नीर-क्षीर विवेक वाक विद्या को सियासतदानों के मन के मुताबिक जैसे तैसे परिभाषित किया। इससे जहां जनता गफलत में रही, वहीं संवैधानिक सिपहसालार मजे में! परन्तु कोढ़ में खाज यह कि जाति/सम्प्रदाय जैसे जनहित के मुद्दे जहां के तहां मील के पत्थर की तरह यथावत बने रहे। इसलिए हमारे राजनेता अपने मन के मुताबिक इनकी तरह तरह की व्याख्या करने में सफल हो जाते हैं, जिससे राष्ट्रहित प्रभावित होता है।

पांचवां, फिलवक्त भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा में कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर जो कुछ भी कहा, वह यदि सही नहीं है तो ज्यादा गलत भी नहीं है! लिहाजा, इस मुद्दे पर आधुनिक सोच विकसित करनी चाहिए। साथ ही कतिपय संवैधानिक/कानूनी कमियों को दूर किया जाना चाहिए, ताकि कभी भारतीय समाज को माला की तरह जोड़ने वाली जाति प्रथा आरक्षण उत्प्रेरित सामाजिक टूट की वजह न बन जाये। जैसा कि महसूस किया जा रहा है।इसलिए आरक्षण के आधार को जाति-धर्म-भाषा नहीं बल्कि आर्थिक आधार का किया जाना चाहिए, इसे रोटेशनल बनाकर सबको लाभान्वित किया जाना चाहिए, जो न्यायिक तर्क/वितर्क के मद्देनजर आसान नहीं लगता है।

छठा, उल्लेखनीय कि 30 जुलाई 2024 मंगलवार को अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि, जिन्हें अपनी जाति के बारे में भी नहीं पता है वो जाति जनगणना की बात करते हैं। यह बात एक हद तक सही भी प्रतीत हो रही है! इसलिए ऐसे लोगों की जाति व धर्म के लिए भारत में स्पष्ट कानूनी प्रावधान तय किए जाने की जरूरत है, जो तर्क और तथ्य की कसौटी पर खरा हो। क्योंकि वैदिक जाति या धर्म की अवधारणा पूरी तरह से वैज्ञानिक है, जिसकी उपेक्षा संवैधानिक भारत में होना आम बात बन चुकी है।

सातवां, राहुल गांधी पर सदन में हमला बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने इसके पहले ये भी कहा था कि असत्य के पैर नहीं होते हैं, जिसके चलते ये कांग्रेस के कंधे पर सवारी करता है। जैसे मदारी के कंधे पर बंदर सवारी करता है, वैसे ही राहुल गांधी के कंधे पर असत्य का बंडल होता है। तभी तो अनुराग ठाकुर की इन टिप्पणियों पर सदन में हंगामा बढ़ गया। इसलिए सीधा सवाल है कि अनुराग ठाकुर के इस बयान के बाद सदन में जो जमकर हंगामा शुरू हो गया और कांग्रेस के सांसद वेल में आकर प्रदर्शन करने लगे, वह कितना जायज है? क्या इसे टाला नहीं जा सकता है। यदि जनप्रतिनिधिगण हंगामा करने के बजाय तत्सम्बन्धी कानून बनाने की मांग करें तो ऐसे विरोधाभासों को टाला जा सकता है।

आठवां, संयुक्त विपक्ष हंगामा करने के बजाय उन लोगों की एक अलग जातीय कोटि व धार्मिक कोटि बनाने की मांग करे, जिनके माता-पिता भिन्न-भिन्न जातियों या सम्प्रदायों से है, क्योंकि उनकी संतान वर्णसंकर हुई। चूंकि भारतीय समाज पितृसत्तात्मक समाज है, इसलिए यहां पिता की जाति या धर्म को स्वीकार करने की परम्परा प्रचलित है, जो तर्क और तथ्य की कसौटी पर पूरी तरह से गलत है। क्योंकि इससे सम्बन्धित जाति/धर्म का मूलगुण दूषित/भ्रमित होता है। इसी तरह से साधुओं की भी एक अलग जाति बनाने की जरूरत है।

नौवां, आप मानें या न मानें, किंतु वैदिक साहित्य में ऐसे लोगों के लिए ही वर्णसंकरता की परिकल्पना मौजूद है, जिसकी चतुराई और उसके संभावित दुष्परिणामों के बारे में वैदिक साहित्य द्वारा पहले ही आगाह किया जा चुका है। हालांकि, तथाकथित प्रगतिशील वामपंथी लोगों के पास स्वस्थ सामाजिक-सांस्कृतिक चिंतन का अभाव होने के चलते न तो वर्णसंकर लोगों की अलग जाति तय हुई और न ही अंतरधार्मिक शादी-विवाह करने वालों के लिए अलग धर्म तय किया गया। जबकि भारतीय समाज में इन्हें कहीं दोगलवा तो कहीं दुगामिया कहे जाने की परंपरा प्रचलित है, जिसे अबतक कानूनी वर्गीकरण हासिल नहीं है। इसलिए उम्मीद है कि इस बहस के बाद इनका भी कानूनी वर्गीकरण किया जाना चाहिए और ऐसे तमाम लोगों को जातीय आरक्षण से वंचित किया जाना चाहिए या फिर किस कोटि से दिया जाए, उसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

दसवां, सच तो यह है कि संसद के मॉनसून सत्र के दौरान जातीय जनगणना को लेकर अनुराग ठाकुर के बयान पर जो संग्राम मचा हुआ है, वह आगामी विधानसभा चुनावों व यूपी उपचुनाव के दृष्टिगत विपक्ष की एक सुनियोजित सियासी रणनीति है। इन सबके पीछे विपक्षियों की मौके पर चौका लगाने वाली रणनीति काम कर रही है, जिसके चलते 10 साल बाद ही सही पर वह संसद में मजबूत होकर लौटा है। तभी तो संयुक्त विपक्ष ने अनुराग ठाकुर के बयान को लेकर सदन में जमकर बवाल काटा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी रही। विपक्ष के नारों का शोर बढ़ा और विपक्षी सदस्य 'वी वांट कास्ट सेंसस' के पोस्टर जब लहराने लगे, तब स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोका। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही भी कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी।

ग्यारहवां, बीजेपी सांसद कांग्रेस पार्टी के सांसदों की हरकत की निंदा करते हुए अनुराग ठाकुर के बयान को सही बता रहे हैं। बीजेपी भी जातीय जनगणना मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर देश में अराजकता भड़काने का आरोप लगाया। वहीं, भाजपा सांसद अरुण गोविल ने भी राहुल गांधी की समझ पर सवाल उठाया है। मेरठ से भाजपा सांसद अरुण गोविल ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी के बारे में कुछ भी कहना अजीब सा है। मुझे समझ नहीं आता कि वह बात को किस तरह से लेते हैं, किस तरह से समझते हैं क्योंकि वह बात को कहीं और ले जाते हैं। वह कहना कुछ चाहते हैं लेकिन कहते कुछ और हैं। वहीं, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी अनुराग ठाकुर के बयान को उचित बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो हरकत की है मैं उसकी निंदा करता हूं। कांग्रेस दिन-रात जाति-जाति करती रहती है। कांग्रेस ने जाति पूछ-पूछकर देश को बांटने की साजिश की है और जब सदन में जाति की बात हुई तो राहुल गांधी हंगामा कर रहे हैं। इन लोगों ने देश को कमजोर करने के लिए एक साजिश रची हुई है। ये देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। राहुल गांधी को किसने हक दिया कि वह सबसे जाति के बारे में पूछे और उनसे कोई उनकी जाति के बारे में नहीं पूछ सकता। ये गंभीर मामला है। हम देश को टूटने नहीं देंगे, हम देश को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे।

बारहवां, उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है कि जातीय राजनीति अब चुनाव मैदान होते हुए देश की संसद तक पहुंच चुकी है। यूपी में समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की सफलता ने पूरे देश में ऐसी गोलबंदी को शह देने के रास्ते खोल दिए हैं। इसलिए ऐसी बहस सीधे विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आमने-सामने हो रही है। जिसकी शुरुआत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने की, और फिर अनुराग ठाकुर ने मोर्चा संभालकर उसमें तड़का लगा दिया।

-:सौजन्य:-
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV
Drive the Future

पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को मिलेगी एमजी की चमचमाती इलेक्ट्रिक कार

परिवहन विशेष न्यूज

पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को चमचमाती इलेक्ट्रिक कार गिफ्ट की जाएगी। जेएसडब्लू ग्रुप के चेयरमैन और एमडी सज्जन जिंदल ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि भारत के हर ओलंपिक पदक विजेता को एमजी विंडसर ईवी कार दी जाएगी। अब तक देश के तीन निशानेबाज कांस्य पदक जीत चुके हैं। कई और खिलाड़ियों से पदक की उम्मीद है।

सज्जन जिंदल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा- 'यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि जेएसडब्लू एमजी इंडिया टीम इंडिया के हर ओलंपिक पदक विजेता को एक शानदार कार एमजी विंडसर उपहार में देगी। हमारे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अपने समर्पण और सफलता के लिए सर्वश्रेष्ठ के हकदार हैं!'

थाईलैंड हाइब्रिड कार निर्माताओं से निवेश आकर्षित करने के लिए नए टैक्स ब्रेक लागू करने की बना रहा योजना

परिवहन विशेष न्यूज

थाईलैंड अगले चार वर्षों में नए निवेश में कम से कम 50 बिलियन थाई बहत ($1.4 बिलियन) आकर्षित करने के लिए हाइब्रिड कार निर्माताओं को नए प्रोत्साहन देने की योजना बना रहा है।

थाईलैंड की राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन नीति समिति के सचिव, नरीत थेर्डस्टीरासुकडी ने बीती 26 जुलाई को संवाददाताओं से कहा कि यदि हाइब्रिड वाहन निर्माता कुछ मानकों को पूरा करते हैं तो उन्हें 2028 और 2032 के बीच कम उपभोग कर की दर का भुगतान करना होगा।

नरीत ने कहा कि 10 से कम सीटों वाले योग्य हाइब्रिड वाहन 2026 से 6% उत्पाद कर की दर के अधीन होंगे और हर दो साल में दो प्रतिशत-अंक की फ्लैट दर वृद्धि से छूट दी जाएगी।

कम कर दर के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए हाइब्रिड कार निर्माताओं को अब से 2027 के बीच थाईलैंड के इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में कम से कम 3 बिलियन baht का निवेश करना होगा। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम के तहत उत्पादित वाहनों को सख्त कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, इकट्ठे या निर्मित प्रमुख ऑटो पार्ट्स का उपयोग करना होगा थाईलैंड में और छह निर्दिष्ट उन्नत ड्राइवर सहायता प्रणालियों में से कम से कम चार से सुसज्जित होना चाहिए।

नरीत ने कहा कि थाईलैंड में पहले से ही काम कर रहे सात हाइब्रिड कार निर्माताओं में से कम से कम पांच के इस परियोजना में

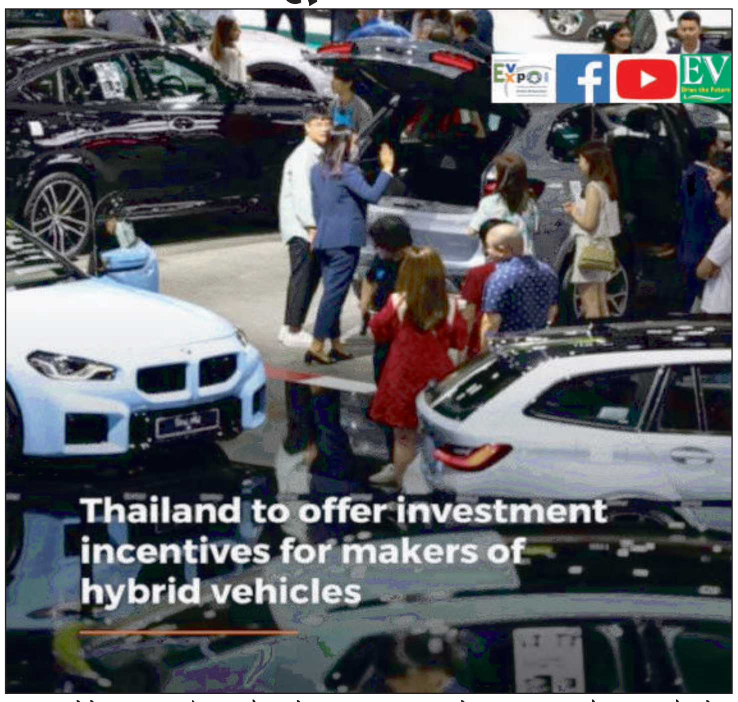

शामिल होने की उम्मीद है। थाईलैंड इलेक्ट्रिक वाहन समिति का निर्णय समीक्षा और अंतिम अनुमोदन के लिए कैबिनेट को प्रस्तुत किया जाएगा।

नरीत ने कहा ₹यह नया उपाय थाई ऑटोमोटिव उद्योग के विद्युतीकरण में परिवर्तन और संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के भविष्य के विकास का समर्थन करेगा। थाईलैंड में पूर्ण वाहनों और घटकों सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उत्पादन केंद्र बनने की क्षमता है।"

नई योजनाएं तब आई हैं जब थाईलैंड ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आक्रामक रूप से प्रोत्साहन पेश किया है, जिसने हाल के वर्षों में विशेष रूप से चीनी निर्माताओं से महत्वपूर्ण विदेशी निवेश आकर्षित किया है। ₹एशिया के डेट्रॉइट₹ के रूप में थाईलैंड का लक्ष्य 2030 तक अपने वाहन उत्पादन का 30% इलेक्ट्रिक वाहन बनाना है।

थाईलैंड पिछले कुछ दशकों से एक क्षेत्रीय ऑटोमोटिव उत्पादन केंद्र रहा है और टोयोटा मोटर कॉर्प और होंडा मोटर कंपनी सहित दुनिया के कुछ शीर्ष वाहन निर्माताओं के लिए निर्यात आधार रहा है। पिछले दो वर्षों में बीवाईडी और जैसे चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं द्वारा निवेश किया गया है। ग्रेट वॉल मोटर्स ने थाईलैंड के ऑटोमोबाइल उद्योग में भी नई ऊर्जा ला दी है।

थाई सरकार ने आयात और उपभोग करों को कम कर दिया है और स्थानीय उत्पादन शुरू करने के लिए वाहन निर्माताओं की प्रतिबद्धता के बदले कार खरीदारों को नकद सब्सिडी की पेशकश की है, जो थाईलैंड को एक क्षेत्रीय ऑटोमोटिव केंद्र के रूप में पुनर्जीवित करने के नवीनतम कदम में है। इस पृष्ठभूमि में थाई बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ी है।

नरीत के अनुसार थाईलैंड ने 2022 से 24 इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं से निवेश आकर्षित किया है। इस वर्ष की पहली छमाही में थाईलैंड में नए पंजीकृत बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़कर 37,679 हो गई, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 19% की वृद्धि है।

बीते 25 जुलाई को फेडरेशन ऑफ थाई इंडस्ट्रीज द्वारा जारी ऑटो बिक्री आंकड़ों से यह भी पता चला कि इस साल की पहली छमाही में थाईलैंड में सभी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 41% बढ़ी, जो 101,821 वाहनों तक पहुंच गई। इसी समय थाईलैंड में कुल घरेलू वाहन बिक्री में 24% की गिरावट आई, जिसका मुख्य कारण पिकअप ट्रकों और आंतरिक दहन इंजन यात्री कारों की कम बिक्री थी।

छह एयरबैग के साथ आती हैं ये पांच एसयूवी, कीमत 10 लाख रुपये से है कम

परिवहन विशेष न्यूज

भारत में वाहन निर्माता अब बेहतरीन फीचर्स के साथ ही वाहनों को सुरक्षित बनाने पर भी ध्यान दे रहे हैं। कुछ समय पहले तक महंगी कारों में ही ज्यादा एयरबैग दिए जाते थे, लेकिन अब कम कीमत वाली एसयूवी में भी छह एयरबैग ऑफर किए जाते हैं।

हुंडई मोटर्स की ओर से भारतीय बाजार में एक्सटर एसयूवी को ऑफर किया जाता है। कंपनी की इस एसयूवी में छह एयरबैग ऑफर किए जाते हैं। यह सेफ्टी फीचर एसयूवी में स्टैंडर्ड तौर पर दिया जाता है। जिसका मतलब है कि इसके बेस वेरिएंट में भी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। छह एयरबैग के साथ आने वाली यह देश की सबसे सस्ती एसयूवी है। इसकी कीमत 6.12 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू हो जाती है।

महिंद्रा की ओर से अप्रैल के आखिर में एक्सयूवी 3एक्सओ को लॉन्च किया गया था। कंपनी की यह एसयूवी छह एयरबैग के साथ आती है। कंपनी ने इसे 7.49 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर भारतीय बाजार में ऑफर किया है।

हुंडई की ओर से एक्सटर के साथ ही वेन्यू को भी छह एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर के साथ ऑफर किया जाता है। 10 लाख रुपये से कम कीमत पर मिलने वाली इस एसयूवी में कई और फीचर्स को भी दिया जाता है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 7.94 लाख रुपये से शुरू हो जाती है।

किआ की ओर से भी सोनेट एसयूवी को बेहतरीन फीचर्स और सेफ्टी के साथ ऑफर किया जाता है। वेन्यू की तरह ही इसमें भी छह एयरबैग ऑफर किए जाते हैं। एसयूवी के सभी वेरिएंट में इस फीचर को दिया जाता है। किआ सोनेट की एक्स शोरूम कीमत 7.99 लाख रुपये से शुरू होती है।

टाटा की ओर से नेक्सन एसयूवी को ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी को कंपनी की ओर से कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में लाया जाता है। सेफ्टी के लिए इसमें भी छह एयरबैग मिलते हैं। इसकी एक्स शोरूम कीमत भी 7.99 लाख रुपये से शुरू हो जाती है।

2025 BYD Seagull ev हुई लॉन्च, सिंगल चार्ज में देगी 405km की रेंज

परिवहन विशेष न्यूज

2025 BYD Seagull को लॉन्च कर दिया गया है। इसे पिछले वाले से थोड़ा अपडेट करके लॉन्च किया गया है। इसमें नए पावरट्रेल ऑप्शन के साथ डिजाइन में थोड़ा बदलाव किए गए हैं। इतना ही नहीं पैसेंजर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कई सुरक्षा फीचर्स भी दिए गए हैं। इसका इलेक्ट्रिक मोटर 4.9 सेकंड में 0 से 50 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है।

नई दिल्ली। चीन में BYD Seagull लॉन्च होने के बाद से ही इसकी चर्चा हर जगह पर हो रही है। अब कंपनी 2025 BYD Seagull के रूप में थोड़ा अपग्रेड मॉडल को लॉन्च किया है। इसमें नए ट्रिम लेवल और पावरट्रेन ऑप्शन के साथ डिजाइन रिफ्रेश मिलता है। आइए जानते हैं कि इसे किन नए फीचर्स के साथ लाया गया है।

2025 BYD Seagull के फीचर्स

इसके बेस विटैलिटी एडिशन में व्हील कवर के साथ 15 इंच स्टील व्हील मिलते हैं, जबकि फ्रीडम एडिशन और फ्लाइंग एडिशन में 16-इंच एल्युमीनियम अलॉय व्हील दिए गए हैं। इसे चार कलर ऑप्शन आर्कटिक ब्लू, वार्मसन व्हाइट, पोलर नाइट ब्लैक और पीच पिंक में लाया गया है। BYD इंटीरियर कलर ऑप्शन डीप ओशन ब्लू और ड्यून पिंक में भी है। इसमें फ्रीडम एडिशन और फ्लाइंग एडिशन मोबाइल वायरलेस चार्जर, हीटेड फ्रंट सीट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 7-इंच इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन और 10.1-इंच रोटेटेबल इंफोटेनमेंट स्क्रीन जैसे फीचर्स से लैस किया गया है।

कैसा है इंजन

इसके बेस विटैलिटी एडिशन और मिड-स्पेक फ्रीडम एडिशन में एक छोटा 30.08 kWh बैटरी पैक दिया गया है। जिसे एक बार चार्ज होने के बाद करीब 305 किमी तक का सफर तय किया जा सकता है। वहीं, इसके टॉप-स्पेक फ्लाइंग एडिशन में 38.8 kWh बैटरी पैक दिया गया है, जिसे एक बार चार्ज करने के बाद 405 किमी तक का सफर तय किया जा सकता है। इसका इलेक्ट्रिक मोटर 4.9 सेकंड में 0 से 50 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है।

कितनी है कीमत

2025 BYD Seagull में एक छोटा बैटरी पैक ऑप्शन है। इसके 30.08 kWh बैटरी पैक वाली की कीमत CNY 69,800 (8 लाख रुपये) से शुरू होती है। इसके टॉप-स्पेक फ्लाइंग एडिशन में बड़ी 38.88 kWh बैटरी पैक वाले की कीमत CNY 85,800 (10 लाख रुपये) है। इसके फेसलिफ्ट के साथ डिजाइन में बदलाव की बात है, तो सामने कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके पीछे बिल्ड योर ड्रीम्स लेटरिंग को BYD लेटरिंग से बदल दिया गया है।

कनाडाई यूनियन यूनिफोर ने आयातित चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर सख्त टैरिफ लगाने की मांग की

परिवहन विशेष न्यूज

कनाडाई श्रमिक संघ यूनिफोर ने गुरुवार, 01 अगस्त को संघीय सरकार से सभी चीनी निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों, ईवी बैटरी और अन्य घटकों पर टैरिफ लगाने का आह्वान किया, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पहले से प्रस्तावित कुछ उपायों के अनुरूप है।

जुलाई में, कनाडा ने सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया शुरू की थी, क्योंकि वह संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा इसी प्रकार के कदम उठाए जाने के बाद, चीनी निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा था।

कनाडा सरकार ने कहा है कि उसे ₹यह जोखिम दिखाई देता है कि यदि इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के लिए चीन के अनुचित समर्थन पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो इससे आयात में अत्यधिक वृद्धि हो सकती है, जिसका नियोजित इलेक्ट्रिक वाहन निवेश और कनाडा के मोटर वाहन क्षेत्र के परिवर्तन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

निजी क्षेत्र के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली कनाडा की सबसे बड़ी यूनियन यूनिफोर ने गुरुवार, 01 अगस्त को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने अनुचित आयात से उत्पन्न खतरे पर सक्रिय प्रतिक्रिया दी है और अब समय आ गया है कि कनाडा भी ऐसा ही करे।

यूनिफोर ने मांग की है कि कनाडा चीनी निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% की मौजूदा टैरिफ दर से अतिरिक्त कर तथा बैटरियों पर 25% का अतिरिक्त कर लगाए, साथ ही इलेक्ट्रिक मोटरों और बैटरी सेल सामग्रियों पर भी अतिरिक्त शुल्क लगाए।

जबकि कनाडा संभावित टैरिफ की जांच कर रहा है, दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं में से एक, चीनी वाहन निर्माता बीवाईडी ने हाल ही में कनाडा सरकार के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैरिफ के संभावित अनुप्रयोग और कनाडा में यात्री इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री शुरू करने की अपनी योजना पर चर्चा की।

सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने मुख्य सड़कों पर गैर-पंजीकृत ई-रिक्शा के चलने पर लगाई रोक

परिवहन विशेष न्यूज

सिलीगुड़ी की मुख्य सड़कों पर गैर-पंजीकृत ई-रिक्शा के चलने पर रोक लगा दी गई है। यह निर्णय सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने यातायात की भीड़ को कम करने के प्रयास में लिया गया है।

शहर में ई-रिक्शा के मुद्दे पर मेयर गौतम देब और पुलिस आयुक्त तथा यातायात के डीसीपी सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के बीच हाल ही में हुई बैठक के बाद यह पहल शुरू की गई है।

गुरुवार, 01 अगस्त की सुबह से गैर-पंजीकृत ई-रिक्शा को हिलकार्ट रोड, सेवोके रोड और बिधान रोड जैसी मुख्य सड़कों के साथ-साथ विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा शहर की आंतरिक सड़कों पर भी ई-रिक्शा के चलने पर रोक लगा दी गई है।

इस दिन यातायात प्रहरियों ने इस प्रतिबंध को लागू करने और गैर-पंजीकृत ऑटो को चलने से रोकने के लिए अभियान चलाया है। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि यह अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा।

वित्त वर्ष 2024 में ईवी पंजीकरण 43 प्रतिशत से अधिक बढ़ा, 17,896 करोड़ रुपये का निवेश: केंद्र

परिवहन विशेष न्यूज

वित्त वर्ष 2023 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में 42.06 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारी उद्योग और इस्पात राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने राज्यसभा को बताया कि वित्त वर्ष 2024 में ई-वाहन पोर्टल पर 16,81,127 ईवी पंजीकृत किए गए, जबकि वित्त वर्ष 2023 में ऐसे 11,83,341 वाहन थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, सोमवार, 29 जुलाई तक ई-वाहन पोर्टल पर कुल 45,74,938 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत किए गए हैं।

सरकार ने 2021 में 25,938 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिये उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। मंत्री ने कहा, ₹जैसा कि योजना के तहत अनुमोदित आवेदकों द्वारा रिपोर्ट किया गया है, 31 मार्च, 2024 तक निवेश 17,896 करोड़ रुपये है और वृद्धिशील बिक्री 3,370 करोड़ रुपये है।

सरकार ने यह भी बताया कि पीएलआई-ऑटो योजना के लिए वित्त वर्ष 2025 पहला प्रोत्साहन संवितरण वर्ष है।

पीएलआई-ऑटो योजना के तहत गुजरात में 12 विनिर्माण स्थानों के साथ 10 अनुमोदित आवेदक हैं। मंत्रालय ने भारत में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए 2015 में फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया यानी फेम इंडिया योजना शुरू की थी। फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत, 6,825 करोड़ रुपये के 16,71,606 इलेक्ट्रिक वाहनों के दावे ओईएम यानी ईवी निर्माताओं द्वारा सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत किए गए हैं।

केंद्र ने कहा कि फेम 2 योजना के तहत इंट्रा-सिटी संचालन के लिए 6,862 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी गई थी। 6,862 ई-बसों में से 31 जुलाई तक 4,853 ई-बसों की आपूर्ति की जा चुकी है। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में और तेजी लाने के लिए सरकार फेम 3 लॉन्च करने की योजना बना रही है।

बढ़ती आबादी और घटते संसाधन

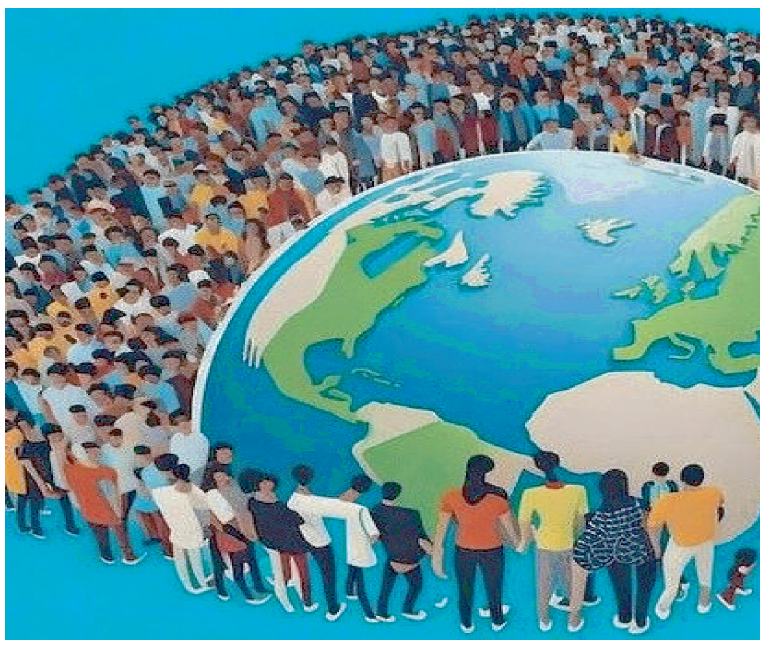

विजय गर्ग

रपट के अनुसार युद्धग्रस्त गाजा पट्टी और सूडान में बिगड़े खाद्य सुरक्षा के कारण 2022 2.4 करोड़ से भी अधिक लोगों को भोजन के अभाव में भूखे रहना पड़ा था। देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र की रपट इस बात की ओर साफ संकेत करती है कि जैसे-जैसे विश्व की जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे- -वैसे लोगों की संख्या में भी लगातार वृद्धि होती गई।

बेतहाशा बढ़ती आबादी आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है।

दुनिया के कई देशों बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में वहां उपलब्ध संसाधन अब कम पड़ने लगे हैं। जाहिर है कि अगर किसी भी देश की जनसंख्या लगातार तीव्र गति से बढ़ेगी, तो उसी अनुपात में वहां उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव भी बढ़ेगा। इसे भारत के संदर्भ में देखा जाए तो 7 जुलाई, 2024 को भारत की जनसंख्या एक अरब 44 करोड़ 19 लाख 10,332 थी। यह दुनिया की कुल जनसंख्या (8.119 अरब) का लगभग 18.02 फीसद भू-भाग पर जो विश्व के महज ढाई फीसद पर जीवन यापन करने को विवश है। इसी वर्ष अप्रैल के अंत में जारी संयुक्त राष्ट्र की खाद्य संकट पर वैश्विक रपट के अनुसार आज दुनिया भर के 59 देशों के लगभग 28.2 करोड़ लोग भूखे रहने को मजबूर हैं।
रपट के अनुसार युद्धग्रस्त गाजा पट्टी और सूडान में बिगड़े खाद्य सुरक्षा के कारण 2022 2.4 करोड़ से भी अधिक लोगों को भोजन के अभाव में भूखे रहना पड़ा था। देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र की रपट इस बात की ओर साफ संकेत करती है कि जैसे-जैसे विश्व की जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे- -वैसे लोगों की संख्या में भी लगातार वृद्धि होती गई। भोजन के अभाव पर संयुक्त राष्ट्र की पहली रपट 2016 आई थी, जिसकी तुलना में ताजा रपट में विश्व भर में भूखे लोगों की में चार वृद्धि हो चुकी है। गौरतलब गुना संख्या कि बढ़ती जनसंख्या 'जनसंख्या के अनुपात में सभी नागरिकों के भोजन, वस्त्र, आवास, पेयजल, चिकित्सा व्यवस्था, दवाइयां आदि मूलभूत आवश्यकताओं की सरल काम नहीं है। बढ़ती आपूर्ति करना किसी भी सरकार के लिए आबादी के कारण ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों है, तेल और प्राकृतिक कोयला, तेल प्राकृतिक गैसों आदि पर भी अत्यधिक दबाव बढ़ गया, जिसे कम कर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश और उपयोग करना जरूरी है।
अर्थशास्त्री थामस राबर्ट माल्थस ने सन 1798 में गणितीय रूप से भोजन और मानव जनसंख्या के बीच संबंधों पर विचार करके बाद बताया था कि खाद्य आपूर्ति बढ़ने से जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। से बढ़ती है और उपलब्ध संसाधनों धनों को समाप्त कर र देती है. x जसके परिणामस्वरूप मानव पीड़ा बनी रहती है. जब तक कि जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया जाता। 1888 में तत्कालीन वायसराय लार्ड डफरिन ने यह आशंका व्यक्त की थी कि भारत में कृषि उत्पादन कम है और तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण यहां अकाल पैदा होता है। इसके बावजूद 1871 से 1941 तक भारत की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 0.60 फीसद रही, जबकि दुनिया का औसत 0.69 फीसद था। हालांकि बीसवीं सदी के प्रथम दो दशकों में जनसंख्या वृद्धि दर अपेक्षाकृत कम रही। 1931 1931 की जनगणना में सामने आया कि भारत में 1921-1931 के बीच प्रतिवर्ष एक फीसद की दर से जनसंख्या बढ़ी है, सभी चौंक गए, लेकिन 1951 के बाद यह दर लगभग दो फीसद के आसपास पहुंच गई। वैसे 1970 के दशक से देश की जनसंख्या वृद्धि दर में निरंतर गिरावट आई है, जो संभवतः पिछले कुछ दशकों में शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर में किए गए सुधारों का परिणाम है, क्योंकि अब तक जनसंख्या वृद्धि की दर सर्वाधिक उन्हीं क्षेत्रों में पाई गई है, जहां लोग शिक्षित और स्वस्थ नहीं होते। हालांकि यह गिरावट अपेक्षाकृत काफी धीमी रही है आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों पर गौर करें तो भारत में वर्ष 1971-81 के बीच 2.5 फीसद रही वार्षिक जनसंख्या वृद्धि की दर 2011 16 के मध्य तक आते-आते 1.3 फीसद रह गई। इसका दूसरा पक्ष यह है कि जनसंख्या बढ़ने और संसाधनों के घटने से देशों पर कर्ज का बोझ भी बढ़ने लगता है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रपट के अनुसार सितंबर 2023 तक भारत पर कुल कर्ज का बोझ 205 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। वहीं, विश्व आर्थिक मंच की 2021 में जारी एक रपट के अनुसार शिक्षा गुणवत्ता में भारत का स्थान नब्बेवां है। जनसंख्या संबंधी संयुक्त राष्ट्र की 15 नवंबर, 2022 को जारी एक रपट के अनुसार 2027 भारत चीन को पछाड़ देगा, जबकि संयुक्त राष्ट्र के आकलन को झुठलाते हुए अप्रैल 2023 में ही चीन को पछाड़ कर भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया। फरवरी 2024 में संयुक्त राष्ट्र ने ही अपनी एक अन्य रपट जारी की थी। हालांकि 2011 क। के बाद से भारत में जनगणना नहीं हुई है। बहरहाल, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न बेरोज बेरोजगारी, भुखमरी, x कुपोषण, बीमारी, गरीबी, लाचारी आदि ऐसी समस्याएं हैं, जो किसी भी समाज के नैतिक, सैद्धांतिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक और नैष्ठिक ताने-बाने को ध्वस्त कर सकती हैं। हैं। इसके कारण व्यक्तियों का सामाजिक विकास, सांस्कृतिक उत्थान, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नयन बाधित अगर र ऐसा हुआ ता बाधित हो सकता है। तो समाज में चारों ओर हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार, लूटपाट, चारा, चोरी, झपटमारी, हत्या, आत्महत्या, उग्रवाद और आतंकवाद जैसे अपराधों में बेतहाशा वृद्धि होगी। लोग कानून और लोकलाज की परवाह किए बिना केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति में लग जाएंगे। कमोबेश आज ऐसी ही परिस्थितियों से हमारा देश गुजर रहा है। वैसे, जनसंख्या को लेकर भारत के अनुभवों की बात करें तो गांधी को छोड़कर देश के किसी भी प्रधानमंत्री औरचर्य होता है कि इंदिरा प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सरकार की ओर से कोई कठोर कदम नहीं उठाए गए, जिससे अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लगाई जा सके।। शायद सर सरकारें जनता को जनता का नाराज करण करने से बचती रही होंगी, क्योंकि स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय समाज में यह धारणा व्याप्त थी कि अधिक जनसंख्या विकास का पैमाना है। दरअसल, उन दिनों जनसंख्या का कम होना नकारात्मक परिस्थितियों की देन माना जाता था, जो एक बुरी स्थिति थी, किंतु समय के साथ हमारी सोच बदलाव आता गया और हमने इस पर विचार करना शुरू किया कि क्या भारत इतनी बड़ी जनसंख्या को संभालने में सक्षम है। समय-समय पर आने वाले भयानक सूखे और अकाल की त्रासदी ने भी इस चिंता को रेखांकित किया। मगर 1970 के दशक तक हमारी सरकारें खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाकर जनसंख्या वृद्धि का समाधान ढूंढ़ती रहीं परिवार नियोजन कार्यक्रम को सख्ती से से अपनाया गया, तो बाद से बढ़ती जनसंख्या पर राजनेताओं ने लोग बेहद नाराज हुए। उसके नें चुप्पी साधना ही बेहतर समझा। भूमंडलीकरण के बाद भी के बाद भी जनसंख्या का मुद्दा भारत में दबा रहा, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री ने 2019 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से जनसंख्या वृद्धि पर चिंता जताई और राज्यों से इसे रोकने के लिए योजनाएं बनाने का आह्वान किया। 2024 का अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने तेजी से बढ़ती आबादी और जनसांख्यिकी में आए बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति बनाने का एलान किया, जो 'विकसित भारत' बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन समस्याओं से निपटने के लिए सुझाव देगी।

संपादक की कलम से

सैलानी संतुष्टि सूचकांक

पर्यटन अगर महज आंकड़ों का खेल है, तो हिमाचल की बुलंदी का सर्टिफिकेट काफी प्रभावशाली है। आधे साल की शुमारी में एक करोड़ पर्यटक किसी भी सूरत इसलिए भी कम नहीं, क्योंकि गोवा में 2023 के पूरे साल का आंकड़ा इससे कहीं आधे पर टिकता है, जबकि राजस्थान में इस दौरान बेशक 18 करोड़ घरेलू व 17 लाख विदेशी सैलानी पहुंचे। पर्यटकों की बढ़ती शुमारी के अनुभव पूरी होटल इंडस्ट्री गिन रही है, फिर भी कुछ आवश्यक पहलू हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पर्यटकों के ये आंकड़े तमाम मंदिरों की परिक्रमा, अटल टनल के दोनों छोरों पर और फोरलेन जैसी सडक़ परियोजनाओं की रफ्तार की कहानी हैं, लेकिन प्रसन्नता यह है कि अब सरकार इसकी केंद्रीय भूमिका में आ रही है। वर्तमान संदर्भ में सुक्खू सरकार ने अपने कार्यकाल में पर्यटक तादाद को पांच करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। जाहिर है इसके पीछे जो सोच रही है, उसके तहत नए निवेश, नई अधोसंरचना, नई व्यवस्था और पर्यटक राज्य की तस्वीर बनाने की महत्त्वाकांक्षा होगी। कांगड़ा को पर्यटक राजधानी बनाने का एक महत्त्वाकांक्षी शीर्षासन, एयरपोर्ट विस्तार को लेकर चल रही कार्रवाई है और अगर इस परिप्रेक्ष्य में सरकार की साधना पूरी हो गई, तो यह परियोजना सारे हिमाचल का युग बदल सकती है। युग बदलने की परिकल्पना में कितना पर्यटन और कैसे पर्यटन पर स्थिति स्पष्ट चाहिए। मसलन पांच करोड़ पर्यटक अगर हर दिन और हर क्षेत्र के हिसाब से गिने जाएं, तो योजनाओं का प्रारूप कालाअंब, जसूर, गगरेट और मैहतपुर से शुरू होगा, वरना मंदिरों में आते हर श्रद्धालु और पर्यटक सीजन की भीड़ में अंधाधुंध विस्तार के मायने अलग होंगे।

हमें पांच करोड़ पर्यटकों को बुलाना नहीं, बल्कि उन्हें संतुष्ट करके वापस भेजना है। अभी तक हमारे पर्यटन की छवि कश्मीर घाटी के बिगड़े मिजाज, देवी दर्शन, अटल टनल के दर्शन, गर्मियों में हिल स्टेशन, ट्रैकिंग, सप्ताहांत भ्रमण और पड़ोसी राज्यों से एक ट्रिप मात्र है। चंडीगढ़ से कसौली या शिमला अब एक दिन की भागमभाग बनता जा रहा है, तो धार्मिक लंगरों में पर्यटन का यात्रा वृतांत महज संख्या बढ़ा रहा है। पर्यटन में गुणवत्ता लाने के लिए हमें एक 'संतुष्टि इंडेक्स' विकसित करना होगा। पर्यटक सीजन की धूल और तमाम गतिविधियों के बीच घूमने-फिरने वालों को अगर गंतव्य स्थलों की स्वच्छता सताएगी, तो बढ़े हुए आंकड़े भी बेमानी होंगे। पांच करोड़ पर्यटकों के लायक संतोषजनक अधोसंरचना, कनेक्टिविटी और मनोरंजन के साधन पुष्ट करने होंगे। सबसे पहले मंदिर दर्शन को दक्षिण भारतीय मंदिरों की तर्ज पर व्यवस्थित तथा आरामदायक बनाना होगा। पांच करोड़ पर्यटकों में अगर हम दस फीसदी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के ले आए, तो मंजिलें बदल जाएंगी, लेकिन इनके लिए कसोल या धर्मकोट नहीं, ट्राइबल, धरोहर, साहसिक व विरासत पर्यटन की तरफ रुख मोडऩा होगा। सुजानपुर, पुराना कांगड़ा, शिमला व मसरूर जैसे स्थलों पर संगीत समारोह, जबकि अनेक स्थानों पर लाइट एंड साउंड कार्यक्रमों की शृंखला बनानी पड़ेगी। हिमाचल की परिवहन सेवाओं की दरों में सहजता तथा विभिन्न स्तरों पर पूरे पर्यटन उद्योग के व्यवहार, दायित्व तथा प्रदर्शन में सुधार लाना होगा। वर्तमान पर्यटन उद्योग के तहत सैलानी संतुष्टि न के बराबर है। बेशक नए आकर्षण उन्हें अवसर प्रदान करेंगे, लेकिन उनके अनुभव को विस्तार देते हुए टिकाऊ तथा सरल बनाने की आवश्यकता रहेगी।

राय

ईमान का दौर डोलते ईमान

विजय गर्ग

कुछ बातें इस युग की नहीं, बीते युग की बातें लगती हैं। इनमें से एक प्रमुख सूत्र वाक्य है- रिश्वत लेना और देना अपराध है। पुराने जमाने में जब कहीं ऐसे रिश्वत के अखाड़े में जाते थे तो वहां, हथकड़ियों में बंधे हुए हाथों के चित्र इस सूत्रवाक्य के साथ दिखाई दे जाते थे। ऐसे चित्र तो आज भी नजर आते हैं, लेकिन इनके हाथों में हथकड़ियां नहीं, बल्कि आशीर्वाद की मुद्रा है कि हे तात! अगर इस राह पर चलोगे, तो ही मंजिल पाओगे। मंजिल जो उनका प्रासाद है। छोटी गाड़ी के बदले बड़ी गाड़ी का चुनाव है और ऐसा लक्ष्य पाणिग्रहण है कि जिसके हाजमे में इस देश का कोई रमणीक स्थल नहीं आता, ऐसी शादियां करने के लिए विदेशी पर्यटन स्थल ललचाने लगे और यहां ये शादियां होती हैं, तो होती ही चली जाती हैं। अब बहुत कुछ बदल गया है। खैर, देश की बात करें। देश की ईमानदारी, कर्त्तव्यनिष्ठा और नैतिक मूल्यों की बात करें। देखते ही देखते कहां खो गए ये सब? जब से इस देश ने होश संभाला है, आजादी के खुलेपन में सांस ली है, तब से यहां हर सरकारी कार्यालय में ऐसे-ऐसे सूचनापट्ट लगे रहते थे कि जिन्हें पढ़कर लगता था कि इस घोर कलियुग में यह सतयुग कहां आ गया? इस सतयुग के एक स्वस्थ और मुक्त सजग प्रहरी बनने की लालसा तब मन में जाग उठती थी। आज किसी के मन में जागती है तो उसे 'बौड़म' कहा जाता है। कभी एक ऐसा साफ-सुथरा माहौल बनाने का सपना था कि जिसमें नैतिक मूल्यों को समर्पित समाज लोगों के दृष्टि बिंब में सदा उभरता रहे और उन्हें 'रामराज लौट आया' कहने की जरूरत भी न पड़े। लोग आदर्श जीवन जीते हुए देश के नव-निर्माण में जुटे रहें। मगर धीरे- धीरे समय की धूल आदर्शों के इस धुले-पुंछे चेहरे पर पड़ती रही। नेता लोग भाषणों, दावों और नारों के साथ आईने साफ करते रहे, लेकिन धूल तो उनके अपने चेहरों पर पड़ी थी। यही कारण रहा कि वक्त बदला और रिश्वत की मनाही करने वाले ये सूचनापट्ट कहीं अपना प्रभाव दिखाते नजर भी नहीं आते। नए शोध ग्रंथों को टटोलते हैं तो पाते हैं कि सच्चाई बदल गई। उसके बदसूरत आंकड़े सबको स्वीकार हो गए। एक बड़ा आंकड़ा यह कि एशिया के सत्रह देशों में रिश्वतखोरी में भारत अव्वल नंबर पर है। जिंदगी तेजी से बदल रही है। कितनी नई बातें हमारी जिंदगी का सामान्य हिस्सा बन गई हैं। उसमें एक बात यह भी है कि इस देश के अधिकांश नागरिक उन सब आजाद बरसों में एक नया सत्य पा गए कि यहां कोई भी काम सीधे और सच्चे रास्ते से नहीं हो सकता। ऐसे रास्तों की तलाश उन फुटपाथी लोगों के लिए बच गई है, जो हर मंजिल को पाने के लिए 'शार्टकट' या संक्षिप्त रास्ते की तलाश करते हैं और सफल होते हैं। कभी कहा जाता था 'प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो-टेढ़ो जाए।' अब बात बदल गई। कहते हैं कि प्यादे से सुल्तान भयो, हर टेढ़े और गलत को सीधा और सही बता कर। चले थे रामयुग की स्थापना के प्रयास में देश की आजादी के बाद। रामयुग तो कहीं आदर्शवाद के चुकते धुंधलके में खो गया। पल्ले आया ऐसा राज, जिसमें भ्रष्ट नेताओं, अफसरों और माफिया की तिकड़ी, जो धड़ल्ले से मनमानी करती है और इसे नव समाज का नाम देती है। तरक्की का मार्ग प्रशस्त होता जा रहा है। अब तो रातोंरात बिसात उलट देने की तरह पांसा बदल देने वाले रंग बदल देते हैं और फिर खुलेआम कामचलाऊ घोड़ों की बोली अरबी घोड़ों के दाम पर लग जाती है। पांच साल राज करने का सपना देख कर आए भद्रपुरुष तड़ीपार हो जाते हैं और मध्यावधि चुनावों का बैंड बाजा बजाने वाले फिर नए ढोल पीटने में व्यस्त होते हैं।

फिर ड्रिल पीरियड, एक सही दिशा : भूपिंदर सिंह

अधिकांश स्कूलों के पास फिटनेस के लिए न तो आधारभूत ढांचा है और न ही कोई कार्यक्रम है। आज का विद्यार्थी फिटनेस व मनोरंजन के नाम पर दूरसंचार माध्यमों का कमरे में बैठ कर खूब दुरुपयोग कर रहा है। ऐसे में विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की बात मजाक लगती है'

वर्षों से स्कूली स्तर पर फिटनेस कार्यक्रम शुरू करने की बात इस कॉलम के माध्यम से हो रही है तथा हमने भी व्यक्तिगत तौर पर प्रदेश के बड़े निजी स्कूलों के प्रबंधकों से कई बार बात की है, मगर हिमाचल प्रदेश का कोई भी सरकारी या निजी स्कूल अपने यहां फिटनेस कार्यक्रम लागू करने में नाकाम रहा है। कई बार नए शिक्षा सत्र शुरू होकर खत्म हो गए, मगर फिटनेस कार्यक्रम कहीं भी शुरू नहीं हो पाया है। मगर इस वर्ष हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के विद्यालयों में विद्यार्थियों की सामान्य फिटनेस के लिए पहले की तरह अनिवार्य रूप से ड्रिल के पीरियड का प्रावधान किया है, पर राज्य में फिटनेस संस्कृति के अभाव में धरातल पर कुछ भी सकारात्मक नजर नहीं आ रहा है। शिक्षा का मतलब शरीर व मन, दोनों का विकास करना है, तो शिक्षण विषयों के रिपोर्ट कार्ड की तरह स्वास्थ्य के मानकों का रिपोर्ट कार्ड भी प्रत्येक विद्यार्थी का हर स्कूल में अनिवार्य रूप से हो, क्योंकि भाषा व अन्य शिक्षण विषयों की तरह ही स्वास्थ्य के मूल स्तंभ स्पीड, स्ट्रेंथ, इडोरैंस व लचक आदि का प्रायोगिक प्रशिक्षण भी इसी उम्र में शुरू करना होता है।

शिक्षण विषयों के लिए तो स्कूलों के पास शिक्षक सहित पूरा प्रबंध है, मगर स्वास्थ्य के घटकों को विकसित करके उनका मूल्यांकन करने की कोई भी सुविधा आज तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इस विषय पर स्कूलों व अभिभावकों को कई बार चेताया जा चुका है, मगर कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी देश को इतनी क्षति युद्ध या महामारी से नहीं होती है, जितनी तबाही नशे के कारण हो सकती है।

आज जब देश के अन्य राज्यों सहित हिमाचल प्रदेश में भी नशा युवा वर्ग पर ही नहीं, किशोरों तक चरस, अफीम, स्मैक, नशीली दवाओं तथा दूरसंचार के माध्यमों के दुरुपयोग से शिकंजा कस रहा है, इसलिए सरकार, स्कूल प्रबंधन व अभिभावकों को इस विषय पर जरूरी कदम जल्दी ही उठा लेने चाहिएं। यदि विद्यार्थी किशोरावस्था में नशे से बच जाता है, तो वह फिर युवावस्था आते-आते समझदार हो गया होता है। माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को विभिन्न विद्याओं में व्यस्त रखने के साथ-साथ शारीरिक फिटनेस की तरफ मोडऩा बेहद जरूरी हो जाता है। मानव का सर्वांगीण विकास शिक्षा के बिना अधूरा है। शिक्षा की परिभाषा में साफ-साफ लिखा है कि यहां शारीरिक व मानसिक दोनों तरह से बराबर विद्यार्थियों का विकास करना है, जिससे वे आगे चलकर जीवन को सफलतापूर्वक खुशहाल जी सकें। शारीरिक विकास के लिए खेलों के माध्यम से फिटनेस कार्यक्रम बहुत जरूरी हो जाता है। खेल ही वह माध्यम है जिसके द्वारा विद्यार्थी को नशे से दूर रखा जा सकता है। पड़ोसी राज्य पंजाब एक समय तरक्की में देश का अग्रणी राज्य रहा है। खेलों में उत्कृष्टता उस प्रदेश की तरक्की व खुशहाली का भी पैमाना होती है। पंजाब में हजारों प्रशिक्षक विभिन्न खेलों में खेल प्रशिक्षण के लिए नियुक्त होने के साथ-साथ खेल प्रशिक्षण के लिए आधारभूत ढांचा होना वहां के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का प्रमुख कारण रहा था। बाद में जब पंजाब धीरे-धीरे खेलों से दूर हुआ तो पहले वहां आतंकवाद और फिर आजकल पंजाब नशे का अड्डा बना हुआ है। यही कारण है कि हर क्षेत्र में आज हरियाणा पंजाब से काफी आगे निकल गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एशियाई, राष्ट्रमंडल व ओलंपिक खेलों में पदक विजेता होने पर खिलाडियों को करोड़ों रुपए के नकद ईनाम व सम्मानजनक नौकरी देकर हरियाणा में खेलों के लिए बहुत ही उपयुक्त बातावरण तैयार किया है। उसी का नतीजा है कि आज हरियाणा का हर किशोर व युवा किसी न किसी खेल के मैदान में नजर आता है।

ग्रामीण विकास से आर्थिक विकास : विजय गर्ग

विजय गर्ग

भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है। सदियों से ग्रामीण क्षेत्रों ने हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संपदा और कड़ी मेहनत करने वाले लोगों को पोषित किया है, लेकिन आज ग्रामीण भारत कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। ग्रामीण गरीबी, ग्रामीण विकास में सबसे बड़ी बाधा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में असमानताएं हैं। सड़कों, बिजली, और सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, कम रोजगार के अवसर, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच आदि कई समस्याएं ग्रामीण जीवन स्तर को प्रभावित करती हैं। रोजगार और बेहतर जीवन स्तर की तलाश में ग्रामीण युवा शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इन चुनौतियों का समाधान करना और ग्रामीण भारत को को समृद्ध बनाना एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। यह केवल सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता, बल्कि ग्रामीण समुदायों, गैर-सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र को भी मिलकर इसके लिए प्रयास करने होंगे।

दरअसल, ग्रामीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को बेहतर बनाने की एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें गांवों का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास शामिल है। आ आर्थिक विकास के अंतर्गत, रोजगार अवसरों में वृद्धि, कृषि उत्पादकता में सुधार और ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा आदि प्रक्रियाएं शामिल हैं। सामाजिक विकास के अंतर्गत, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे तक पहुंच में सुधार करना और राजनीतिक विकास के अंतर्गत ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना तथा उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना आदि है। ग्रामीण विकास दरअसल ग्रामीण गरीबी को कम करने और जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रामीण क्षेत्र, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान करते हैं। कृषि, ग्रामीण उद्योग और गैर-कृषि रोजगार देश के सकल घरेलू उत्पाद। (जीडीपी) में महत्त्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं। ग्रामीण विकास, सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में मदद करता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करके, यानी कृषि, ग्रामीण उद्योग और गैर-कृषि रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर, सामाजिक सेवाओं में करके पानी रक्षा, स्वास्थ्य को ताकत, सीसी सेवाओं तक पहुंच बना कर, बुनियादी ढांचे यानी ग्रामीण क्षेत्राम बिजली और सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास करके, विकास के माध्यम से ग्रामीण युवाओं सशक्त बनाकर तथा ग्रामीण विकास योजनाओं और कार्यक्रमों को बनाने और लागू करने में ग्रामीण समुदायों को शामिल करके, ग्रामीण विकास को गति देने महत्त्वपूर्ण प्रयास किए जा सकते हैं। ग्रामीण विकास योजनाओं और कार्यक्रमों की सफलता के लिए स्थानीय समुदायों का सक्रिय योगदान महत्त्वपूर्ण है।

जब लोग योजनाओं को बनाने और लागू करने में भाग लेते हैं, तो वे उनमें अधिक स्वामित्व की भावना रखते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर कार्यान्वयन होता है। ग्रामीण समुदायों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने से उनका सशक्तीकरण और सामाजिक पूंजी का निर्माण होता है। ग्रामीण समुदायों को योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रबंधन करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करना चाहिए। गांव के लोगों को उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। सड़कें ग्रामीण विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि

वे बेहतर बाजार तक पहुंच प्रदान करती हैं, जिससे किसानों और व्यवसायों को अपनी उपज और उत्पादों को बेचने में आसानी होती है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। कृषि गतिविधियों, लघु उद्योगों और घरेलू उपयोग को बढ़ावा मिले, इसके लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति स्थापित करनी होगी। कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि हो, इसके लिए स्वच्छ पेयजल और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और व्यापार के अवसरों तक पहुंच में सुधार करने के लिए, 'ब्राडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी' प्रदान करना आवश्यक है। उपज के भंडारण के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएं, जिससे फसल नुकसान को कम करने और किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिले। युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करने के के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, जिससे उन्हें बेहतर आजीविका के अवसर प्राप्त सकें। युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा सहित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं का विकास भी आवश्यक है, ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और जीवन स्तर प्राप्त हो सके। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने की पहल की जानी चाहिए। स्थानीय कारीगरों और कलाकारों को बढ़ावा दिया जाए, जिससे उन्हें अपनी कला और शिल्प बेचने के अवसर मिल सके। वनों की कटाई रोकने और वनीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से वन क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। जल प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े उपाय करना तथा वर्षा जल संचयन और सूक्ष्म सिंचाई जैसी तकनीकों को बढ़ावा देकर पानी की कमी को दूर करना जरूरी है। ग्रामीणों को कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना भी जरूरी है, ताकि उन्हें आनलाइन सेवाओं और सूचना तक पहुंच प्रदान की सके। गांवों के विकास के लिए ग्रामीण महिलाओं का सशक्तीकरण और आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के अवसरों को बढ़ाकर ग्रामीणों पलायन करने से रोकना होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों और वहां के लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार को तैयार और क्रियान्वित किया जाना चाहिए। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य बनाने और बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनानी होंगी। महिलाओं को उनके अधिकारों, स्वास्थ्य, स्वच्छता और वित्तीय प्रबंधन के बारे में जागरूक बनाने लिए कार्यक्रम लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण पर जागरूकता अभियान चलाने तथा लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ने और महिलाओं के के प्रति सम्मान को बढ़ावा के लिए सामाजिक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। महिलाओं को लघु हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में स्वरोजगार उद्योग, कृषि, पशुपालन और हस्तशिल्प र स्थापित करने के लिए ऋष्ण, सबसिडी और प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। महिलाओं स्वामित्व वाले व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए, महिला उद्यमियों को बाजार तक पहुंच, क्रेडिट सुविधाओं और सरकारी अनुबंधों में प्राथमिकता प्रदान करनी होगी तथा महिलाओं को रोजगार के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वच्छ जल और स्वच्छता सुविधाओं पहुंच प्रदान करना जरूरी है।

ग्रामीण महिलाओं के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों को दूर करने के लिए लक्षित नीतियां और कार्यक्रम विकसित करना आवश्यक है। भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों और वहां के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना, रोजगार के अवसर पैदा करना, किसानों को सशक्त बनाना तथा गरीबी और असमानता को कम करना है, लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है।

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार मलोट

भारत को 2047 तक विकसित बनाने का लक्ष्य, कितनी मुश्किल होने वाली है राह?

परिवहन विशेष न्यूज

भारत सरकार ने साल 2047 तक देश को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी को ध्यान में रखकर तमाम नीतियां भी बनाई जा रही हैं। लेकिन 2047 तक भारत को विकसित बनाने की राह आसान नहीं होने वाली। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि भारत जैसे सौ अन्य विकासशील देशों ने पिछले दो–तीन दशकों में जो प्रगति की है उसकी रफ्तार लगातार आगे बना कर रखना मुश्किल होगा।

नई दिल्ली। भारत के लिए वर्ष 2047 तक विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होने के लिए अथक प्रयास करने होंगे। विश्व बैंक का मानना है कि राह इसलिए कठिन है क्योंकि भारत जैसे दूसरे सौ विकासशील देशों के लिए भी पिछले दो-तीन दशकों में जो प्रगति की है उसकी रफ्तार लगातार आगे बना कर रखना मुश्किल होगा।

पिछले 50 वर्षों के दौरान दुनिया के हर देश की विकास यात्रा का आकलन करने के बाद विश्व बैंक की नई वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 कहती है कि वैश्विक माहौल इस तरह का बना है कि विकासशील देशों के मध्य आय वर्ग वाले जाल में ही फंस कर रह सकते हैं।

रिपोर्ट कहती है कि कई देश लगातार विकास करते हुए एक ऐसी बिंदु पर पहुंचे हैं जहां उनकी प्रति व्यक्ति जीडीपी अमेरिका के 10 फीसद के करीब हो गया है। यह स्तर फिलहाल 8,000 डॉलर के करीब है। विश्व बैंक इसे मध्य आय वर्ग की श्रेणी में रखता है।

सिर्फ 34 देश मध्यम आय वर्ग से ऊपर

विश्व बैंक के मुताबिक 1136 डॉलर से 13,885 डॉलर प्रति व्यक्ति जीडीपी को मध्यम आय वर्ग वाले देशों में रखा जाता है। वर्ष 1990 के बाद से अभी तक सिर्फ 34 देश ऐसे हैं, जिन्होंने मध्यम आय वर्ग वाले श्रेणी से ऊपर उठ कर उच्च आय वर्ग वाले श्रेणी में शामिल हुए हैं। लेकिन इन 34 देशों में से अधिकांश को यह सफलता इसलिए मिली है कि उन्होंने या तो यूरोपीय संघ में शामिल होना स्वीकार किया है या फिर उन्होंने कच्चे तेल के भंडार से कमाई की है।

इन देशों में अब कई तरह की समस्याएं हैं जैसे इनकी जनसंख्या में बुजुर्गों की संख्या बढ़ने लगी है, विकसित देश अपनी आर्थिक नीतियां बदल रही हैं व संरक्षणवाद को बढ़ावा दे रही हैं। इसी तरह से जिस तरह से ऊर्जा के उपभोग का तरीका बदल रहा है वह भी इन देशों पर बहुत ज्यादा दबाव बनाये हुए है। पहले, विकासशील देशों के लिए विकसित देश बनना आज के मुकाबले ज्यादा आसान था।

क्या दुनिया से दूर होगी गरीबी?

विश्व बैंक कहता है कि दुनिया से गरीबी दूर करने या संपन्नता लाने का लक्ष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि इन मध्य आय वर्ग वाले देशों में कितनी प्रगति होती है। ये देश अभी भी विकास की पुरानी अवधारणा पर निर्भर हैं। इनमें से ज्यादा देशों ने निवेश बढ़ा कर विकास करने की राह चुनी है। जबकि कुछ देशों ने समय से पहले ही प्रौद्योगिकी पर बहुत ज्यादा निवेश कर रखा है।

अब इनको नई सोच अपनाने की जरूरत है। पहले इन्हें निवेश बढ़ाना होगा और उसके बाद प्रौद्योगिकी को अपनाना होगा। खास तौर पर बाहर से प्रौद्योगिकी व निवेश लाने पर ध्यान देना होगा। इसके बाद तीसरे चरण में इन देशों को निवेश, प्रौद्योगिकी और अन्वेषण के बीच सामंजस्य बनाना होगा।

इन देशों के पास गलती करने की गुंजाइश नहीं है। इन देशों को अपने अपने विकास के स्तर के आधार पर उक्त सुझावों को अपनाना होगा। रिपोर्ट तैयार करने वाले निदेशक सोमिक वी लाल का कहना है कि, जो देश सुधार करने और उदारवादी रवैया अपना करने अपनी जनता को थोड़ा कष्ट देने से बचेंगे वह भावी विकास यात्रा से अलग रह जाएंगे।

ITR Filing का बना नया रिकॉर्ड, 31 जुलाई तक 7.28 करोड़ से ज्यादा आईटीआर हुए फाइल

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख खत्म हो गई है। आयकर विभाग ने बताया कि 31 जुलाई 2024 तक 7 करोड़ से ज्यादा करदाताओं ने रिटर्न फाइल कर दिया। इनमें से सबसे ज्यादा रिटर्न न्यू टैक्स रिजीम के तहत फाइल हुआ है। रिटर्न फाइलिंग के मामले में यह अभी तक का सबसे ज्यादा संख्या है।

नई दिल्ली। AY 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख अब जा चुकी है। टैक्सपेयर को 31 जुलाई 2024 (बुधवार) तक रिटर्न फाइल करना था। अगर कोई टैक्सपेयर इस समयसीमा के बाद रिटर्न फाइल करता है तो उसे पेनल्टी का भुगतान करना होगा।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिटर्न फाइल की संख्या के बारे में बताया। आयकर विभाग ने कहा कि 31 जुलाई तक 7.28 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल हो चुके हैं। विभाग द्वारा दिए गए बयान के अनुसार आकलन वर्ष 2024-25 के लिए रिकॉर्ड संख्या में आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल हुए हैं। पिछले साल 6.77 करोड़ रिटर्न फाइल हुए थे।

न्यू टैक्स रिजीम हुए सबसे ज्यादा सेलेक्ट

विभाग के बयान के अनुसार आकलन वर्ष 2024-25 के लिए नयी कर व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत 5.27 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए हैं। वहीं पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) में दाखिल रिटर्न की संख्या 2.01 करोड़ है। भारी रिटर्न फाइल करने की संख्या में आई तेजी कर आधार के विस्तार का एक अच्छा संकेत है।

टाटा मोटर्स के शेयरों में 4 फीसदी की गिरावट, क्या खरीदारी का बन रहा मौका?

टाटा मोटर्स ने गुरुवार को तिमाही नतीजे जारी किए। कंपनी की कुल बिक्री में 11 फीसदी की गिरावट आई और यह जुलाई में सालाना आधार पर 71996 रही। हालांकि जून तिमाही के नतीजे के शानदार रहे। कंपनी का कंसालिडेटेट नेट प्रॉफिट 74 फीसदी बढ़कर 5566 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इसमें जगुआर लैंड रोवर (जगुआर लैंड रोवर) की शानदार बिक्री के साथ अच्छे घरेलू बिजनेस का भी हाथ रहा।

नई दिल्ली। टाटा ग्रुप की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स के शेयरों में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में 4 फीसदी से अधिक की गिरावट देखने को मिली। दरअसल, टाटा मोटर्स की गाड़ियों की बिक्री निवेशकों की उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। कंपनी ने जुलाई में सालाना आधार पर कुल बिक्री में 11 फीसदी की गिरावट दर्ज की है। इससे टाटा मोटर्स शेयरों में जमकर बिकवाली हुई और यह शुरुआती घंटों में 4.09 फीसदी की गिरावट के साथ 1,097.40 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। हालांकि, बाद में इसमें थोड़ी रिकवरी हुई।

कैसे रहे टाटा मोटर्स के तिमाही नतीजे?

टाटा मोटर्स ने गुरुवार को तिमाही नतीजे जारी किए। कंपनी की कुल बिक्री में 11 फीसदी की गिरावट आई और यह जुलाई में सालाना आधार पर 71,996 रही। हालांकि, जून तिमाही के नतीजे के शानदार रहे। कंपनी का कंसालिडेटेट नेट प्रॉफिट 74 फीसदी बढ़कर 5,566 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इसमें जगुआर लैंड रोवर (Jaguar Land Rover) की शानदार बिक्री के साथ अच्छे घरेलू बिजनेस का भी हाथ रहा।

टाटा मोटर्स पर ब्रोकरेज की राय

जेफरीज (Jefferies) ने Buy रेटिंग के साथ टारगेट प्राइस भी 1250 से बढ़ाकर 1330 रुपये कर दिया है। टाटा मोटर्स, नोमुरा और गोल्डमैन सैक्स ने भी टाटा मोटर्स का टारगेट प्राइस बढ़ाया है। टाटा मोटर्स के शेयरों ने पिछले एक महीने में 12 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, पिछले 6 महीने में इससे निवेशकों को 25 फीसदी और एक साल में 77 फीसदी का मुनाफा हुआ है। ब्रोकरेज टाटा मोटर्स पर काफी बुलिश हैं।

डीमर्जर को भी बोर्ड की मंजूरी

टाटा मोटर्स ने बताया कि उसके बोर्ड ने टाटा मोटर्स लिमिटेड (TML) को दो अलग-अलग लिस्टेड कंपनियों में तब्दील करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। इस डीमर्जर स्कीम के तहत TML अपने कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को अलग करेगी। टाटा मोटर्स फिलहाल पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में कार और इलेक्ट्रिक कार बनाती है। वहीं, बस, ट्रक, मिनी ट्रक और पिकअप जैसे कमर्शियल व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है।

डीमर्जर के बाद नए नाम से लिस्टिंग

डीमर्जर के बाद दोनों बिजनेस अलग हो जाएंगे। इसका मतलब कि पैसेंजर व्हीकल का कामकाज टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल (TMPV) के तहत होगा। इसमें जगुआर लैंड रोवर का बिजनेस भी शामिल है।

अमेरिका में मंदी का खतरा: भारत समेत दुनियाभर के शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट, अब आगे क्या?

परिवहन विशेष न्यूज

अमेरिका में विनिर्माण के आंकड़े काफी एक्सपर्ट के अनुमान से काफी कमजोर रहे। इससे अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई। कुछ आर्थिक जानकार अमेरिका में आर्थिक मंदी आने की आशंका भी जता रहे हैं। अमेरिकी बाजार के कमजोर प्रदर्शन का असर भारत समेत दुनियाभर के स्टॉक मार्केट पर पड़ा और उनमें भी भारी गिरावट आई। आइए जानते हैं कि इस वैश्विक गिरावट का क्या असर होने वाला है।

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन बड़ी गिरावट आई। सेंसेक्स अंकों और निफ्टी भारी गिरावट के साथ खुले और आखिर तक रिकवर नहीं कर पाए। सेंसेक्स 885.60 अंक यानी 1.08 फीसदी की गिरावट के साथ 80,981.95 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी ने 293.20 प्वाइंट यानी 1.17 फीसदी का गोता लगाया और 24,717.70 अंकों पर बंद हुआ। अमेरिका, यूरोप और चीन समेत अन्य वैश्विक बाजारों में भी बड़ी गिरावट का रुख दिखा।

भारतीय शेयर बाजार में गिरावट की वजह

- अमेरिकी, यूरोपीय और अन्य एशियाई बाजारों में भारी बिकवाली के चलते भारतीय शेयर मार्केट में गिरावट आई।
- कई कंपनियों के तिमाही नतीजे निवेशकों की उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। इससे भी बिकवाली के ट्रेंड ने जोर पकड़ा।
- मिडल ईस्ट में सप्लाई बाधित होने की चिंता से तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। इससे बाजार का मिजाज खराब हुआ।
- इजरायल और ईरान के बीच तनाव की खबर ने जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ा दी और निवेश का माहौल खराब किया।
- अमेरिकी डॉलर की दरें और ट्रेजरी यील्ड में भी वृद्धि हुई। इससे विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में बिकवाली की।

भारतीय बाजार में अब आगे क्या?

भारतीय शेयर बाजार इस वक्त शायद अपने पीक प्वाइंट पर है। यहां से गिरावट की आशंका से इनकार भी नहीं किया जा सकता। खासकर, कुछ शेयरों का वैल्यूएशन हद से ज्यादा अधिक है। इनमें बड़ी करेक्शन हो सकती है।

कई एक्सपर्ट पहले ही शेयर मार्केट के ऊंचे वैल्यूएशन को लेकर चिंता जता चुके हैं। यहां तक कि बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे में भी बाजार के ऊंचे मूल्यांकन पर रोशनी डाली गई थी। अब कंपनियों के कमजोर तिमाही नतीजों के बीच निवेशकों के भीतर जोश जगाने वाली कोई वजह भी नहीं है।

घरेलू बाजार में व्यापक स्तर पर बिकवाली देखी गई। इससे जाहिर होता है कि मार्केट में आगे की वृद्धि के लिए कोई नया ट्रिगर्स प्वाइंट नहीं है। इसके अभाव में यह थकावट के बिंदु पर पहुंच सकता है। वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनियों की आय अब तक सुस्त ही दिखी है, जबकि व्यापक बाजार मूल्यांकन काफी अधिक बना हुआ है। अमेरिकी आईटी क्षेत्र से कमजोर आय, बेरोजगारी में संभावित वृद्धि, BOJ द्वारा आगे की दर वृद्धि की संभावना और चीन की ग्रोथ में मंदी सभी बाजार की धारणा को कमजोर कर रहे हैं।

18 हजार कर्मचारियों की छंटनी करेगी इंटेल, 1.6 अरब डॉलर का घाटा होने के बाद किया फैसला

टेक इंडस्ट्री में छंटनी का सिलसिला लगातार जारी है। अब अमेरिका की दिग्गज चिप निर्माता इंटेल ने अपने 15 फीसदी कर्मचारियों की छंटनी का करने का फैसला किया है। कंपनी को जून तिमाही में 1.6 अरब डॉलर का घाटा हुआ है। इस घाटे के साथ कंपनी अपने दूसरे खर्चों को भी कम करने की योजना बना रही है। कर्मचारियों की छंटनी इसी योजना का हिस्सा है।

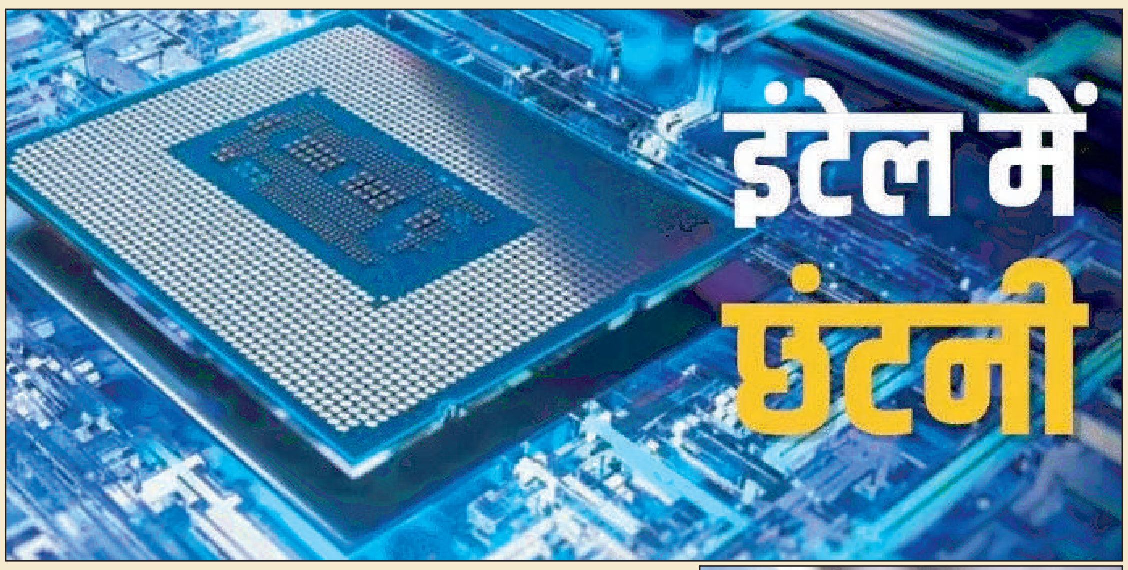

नई दिल्ली। अमेरिकी चिप निर्माता इंटेल अपने 15 फीसदी कर्मचारियों की छंटनी करने वाली है। इंटेल ने जून तिमाही में 1.6 अरब डॉलर का घाटा दर्ज किया। अब कंपनी का मकसद अपने घाटे में कमी लाना और कामकाज को सुव्यवस्थित करना है। यही वजह है कि इंटेल ने इस साल अपने खर्च में करीब 20 अरब डॉलर की कमी लाने की योजना बनाई है। कर्मचारियों की छंटनी भी इसी योजना का हिस्सा है।

इंटेल ने घाटे और छंटनी पर क्या कहा?

इंटेल के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर डेविड जिंसनर ने कहा कि कंपनी अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पीसी प्रोडक्ट का विस्तार कर रही है। लेकिन, इसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही, बहुत-से कर्मचारी ऐसे हैं, जिनका नई टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल हो रहा है। इसका हमारी दूसरी तिमाही की आय पर बुरा असर पड़ा। जिंसनर ने कहा, 'हम अपने व्यय में कटौती करके मुनाफे को बेहतर बनाने और अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए सक्रिय कदम उठा रहे हैं।₹

कितने कर्मचारियों की छंटनी करेगी इंटेल

इंटेल ने पिछले वर्ष के आखिर में बताया था कि उसके पास 1,24,800 कर्मचारी हैं। इसका मतलब है कि कंपनी अपने करीब 18,000 कर्मचारियों को निकाल सकती है। इंटेल ने जून में इजराइल में एक प्रमुख फैक्ट्री प्रोजेक्ट के विस्तार को भी रोक दिया था। उसमें चिप प्लांट के लिए अतिरिक्त 15 अरब डॉलर का निवेश किया जाना था। उसका मकसद भी खर्च को कम करना था।

इंटेल ने छंटनी का एलान ऐसे वक्त में किया है, जब वह एनवीडिया, एएमडी और क्वालकॉम जैसी प्रतिद्वंद्वी कंपनियों से मिल रही चुनौतियों का डटकर मुकाबला कर रही है। उसने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी को भी पेश किया है, जिनके बारे में उसका दावा है कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति की अगुआई करेंगी।

इंटेल के लिए बढ़ रही हैं मुश्किलें

इंटेल ने कई दशकों तक चिप मार्केट पर अपना दबदबा बनाकर रखा। फिर चाहे बात लैपटॉप की बात हो, या फिर डेटा सेंटर की। लेकिन, पिछले कुछ साल में इंटेल के प्रतिस्पर्धी खासकर एआई प्रोसेसर के मामले में इससे आगे निकल गए हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम एनवीडिया का है, जिसके शेयर भी मल्टीबैगर रिटर्न के चलते चर्चा में रहे।

हालांकि, इंटेल ने भरोसा जताया कि वह अपने इनोवेशन के साथ चिप मार्केट में वापस दबदबा बनाने में सफल होगी। इंटेल ने बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का हवाला देते हुए कहा कि

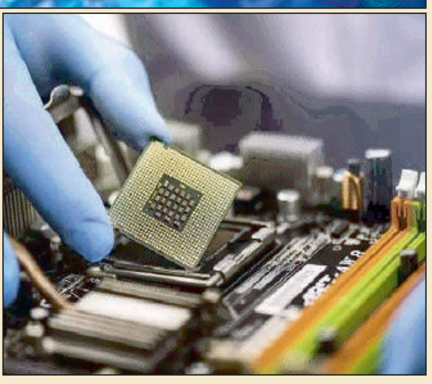

2028 तक एआई कंप्यूटरों का पीसी बाजार में 80 प्रतिशत हिस्सा होने की उम्मीद है।

कंपनी ने कहा, 'कंप्यूटिंग की दुनिया में हो रहे इनोवेशन तरक्की की राह आसान करेंगे। ये मानव क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाएंगे और आने वाले वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान करेंगे।'

आईपीओ लाने के प्रोसेस को सरल कर रहा सेबी, AI की भी ली जाएगी मदद

आईपीओ प्रक्रिया के इर्द–गिर्द एक जटिलता कायम है। जैसे कि एक जटिल ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट्स दाखिल करना। अब मार्केट रेगुलेटर सेबी आईपीओ लाने की प्रक्रिया को काफी सरल बनाने जा रहा है। सेबी तेजी से मंजूरी के लिए कंपनियों द्वारा दाखिल किए जा रहे आईपीओ दस्तावेजों की जांच के लिए आर्टिफिशिएल इंटेलिजेंस (एआई) उपकरण भी विकसित कर रहा है। यह उपकरण दिसंबर तक उपलब्ध हो जाएगा।

नई दिल्ली। मार्केट रेगुलेटर सेबी आईपीओ प्रक्रिया के सरलीकरण पर काम कर रहा है। नई प्रक्रिया के तहत एक टेम्पलेट होगा, जहां कंपनियां आईपीओ दस्तावेज तैयार करने के लिए रिक्त स्थान भर सकेंगी। नहीं समझ आने वाली बातों को स्पष्ट करने और किसी विशेष पहलू को समझाने के लिए एक अलग कॉलम होगा। सेबी ने यह भी कहा है कि आईपीओ की कुल संख्या के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष पर है।

फिक्की एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच ने कहा, 'आईपीओ प्रक्रिया के इर्द-गिर्द एक जटिलता कायम है जैसे कि एक जटिल 'ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट्स' दाखिल करना। अब इस प्रक्रिया को इससे मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है।' उन्होंने कहा, 'दस्तावेज सटीक और अर्थपूर्ण होगा तथा इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव को अलग से समझाया जाएगा।'

हालांकि, उन्होंने योजना के क्रियान्वयन के लिए कोई समय-सीमा या इसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी। इसके अलावा सेबी तेजी से मंजूरी के लिए कंपनियों द्वारा दाखिल किए जा रहे आईपीओ दस्तावेजों की जांच के लिए आर्टिफिशिएल इंटेलिजेंस (एआई) उपकरण भी विकसित कर रहा है। यह उपकरण दिसंबर तक उपलब्ध हो जाएगा।

धन जुटाने की नई प्रक्रिया पर काम

कंपनियों के लिए धन जुटाने की एक नई प्रक्रिया पर भी हो रहा काम सेबी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए धन जुटाने की एक नई प्रक्रिया पर भी काम कर रहा है, जो राइट्स इश्यू और तरजीही आवंटन का मिलाजुला रूप होगा। उन्होंने कहा कि तरजीही आवंटन के लिए मंजूरी अवधि वर्तमान में 42 दिन है जो प्रस्तावित नई प्रक्रिया के बाद 23 दिन रह जाएगी। यह धन जुटाने का सबसे तेज तरीका होगा।

दिल्ली का सबसे साफ महीना रहा जुलाई, देश के सर्वाधिक 30 प्रदूषित शहरों में 11 NCR से

परिवहन विशेष न्यूज

जुलाई 2024 में भारत के शीर्ष 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 11 शहर एनसीआर में से रहे हैं। इनमें से सात हरियाणा दो उत्तरप्रदेश और दिल्ली सहित साथ एक शहर राजस्थान में था। इन शहरों की सूची एवं रैंकिंग इस प्रकार थी-
फरीदाबाद (6) रोहतक (8)
मुजफ्फरनगर (9) भिवाड़ी (10) गुरुग्राम (11) चरखी-दादरी (12) धारूहेड़ा (16)
पानीपत (18) बल्लभगढ़ (22)
गाजियाबाद (23) और दिल्ली (26)।

नई दिल्ली। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) के मासिक वायु गुणवत्ता स्नैपशॉट में जुलाई माह के दौरान दिल्ली देश का 26वां सबसे प्रदूषित शहर रहा है। पीएम 2.5 की सांद्रता के हिसाब से 2024 में जुलाई दिल्ली का सबसे साफ महीना रहा।

मासिक औसत के रूप में पीएम 2.5 की सांद्रता 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज की गई, हालांकि यह पिछले साल जुलाई के मुकाबले लगभग 15 प्रतिशत अधिक है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 2024 का यह माह पिछले सालों के मुकाबले 2020 के बाद अब तक का सबसे प्रदूषित जुलाई भी रहा है।

जुलाई 2024 में दिल्ली की पीएम 2.5 सांद्रता राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक के बराबर, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के वार्षिक दिशा-निर्देश का आठ गुना है। इस दृष्टिकोण से सामने आता है कि चरम मानसून के दौरान भी दिल्ली स्वच्छ हवा में सांस नहीं ले पा रही है।

जुलाई 2024 में दिल्ली में सात दिन अच्छे रहे

पीएम 2.5 के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक वर्गीकरण के आधार पर जुलाई 2024 में दिल्ली में सात दिन अच्छे, 21 दिन संतोषजनक और 3 दिन मध्यम श्रेणी में दर्ज किए गए। जुलाई 2024 में 2019 के बाद से जुलाई महीने के लिए मध्यम श्रेणी में दिनों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई, 2019 में मध्यम वायु गुणवत्ता वाले नौ दिन दर्ज किए थे।

30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 11 शहर एनसीआर के

विश्लेषण के अनुसार जुलाई 2024 में, भारत के शीर्ष 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 11 शहर एनसीआर में से रहे हैं। इनमें से सात हरियाणा, दो उत्तरप्रदेश और दिल्ली सहित साथ एक शहर राजस्थान में था। इन शहरों की सूची एवं रैंकिंग इस प्रकार थी- फरीदाबाद (6), रोहतक (8), मुजफ्फरनगर (9), भिवाड़ी (10), गुरुग्राम (11), चरखी-दादरी (12), धारूहेड़ा (16), पानीपत (18), बल्लभगढ़ (22), गाजियाबाद (23) और दिल्ली (26)।

बारिश के कारण वायु गुणवत्ता में सुधार

सीआरईए के विश्लेषक सुनील दहिया ने कहा कि मानसून में हो रही वर्षा के कारण दिल्ली और देश भर के शहरों में वायु गुणवत्ता में कुछ सुधार तो देखा जा रहा है, लेकिन यह वर्षा भी हवा को पूरी तरीके से साफ करने में विफल रही। अभी भी जुलाई में देश के 250 में से केवल पांच शहर ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के वार्षिक मानक पांच माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के दिशानिर्देश का पालन कर पाए।

जुलाई 2024 के दौरान देश के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की रैंक और वहां पीएम 2.5 का स्तर (माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर में)

1. बर्नीहाट 89.9
2. सिवान 75.9
3. मुंगेर 68.4
4. धौलपुर 64.4
5. मंडीगोबिंदगढ़ 58.5
6. फरीदाबाद 55.0
7. श्रीगंगानगर 53.5
8. रोहतक 51.7
9. मुजफ्फरनगर 51.1
10. भिवाड़ी 49.5
11. गुरुग्राम 49.3
12. चरखी दादरी 48.8
13. मुजफ्फरपुर 48.5
14. डूंगरपुर 47.9
15. गुम्मीदीपूंदी 47.8
16. धारूहेड़ा 46.1
17. बददी 45.7
18. पानीपत 43.5
19. लुधियाना 43.4
20. भटिंडा 42.5
21. अमृतसर 41.9
22. बल्लभगढ़ 41.4
23. गाजियाबाद 40.9
24. पूर्णिया 40.7
25. चित्तौड़गढ़ 40.4
26. दिल्ली 40.1
27. जालना 39.4
28. पाली 39.2
29. अम्बाला 39.1
30. हाजीपुर 38.5

एक शराबी पिता द्वारा अपने ढाई साल के बेटे को पांच हजार रुपये में बेचा

मनोरंजन सासमल , स्टेटे हेड उडीशा

भुबनेश्वर : कटक जिले के नियाली इलाके में एक शराबी पिता द्वारा अपने ढाई साल के बेटे को पांच हजार रुपये में बेचने की घटना से हड़कंप मच गया है। खबर सामने आने के बाद अबिवेक के पिता ने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने बच्चे को बेच दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक, 35 साल का सुकांत सिंह कटक जिले के नियाली पुलिस इलाके के बगीचा बस्ती मुंडासाही इलाके में रहता है। पिछले तीन वर्षों से स्टेशन पर उनके 6 बच्चे हैं। सुकांत सिंह की पत्नी की दो साल पहले मौत हो गयी थी। सुकांत सिंह का घर मयूरभंज जिले के दुर्गा देवी इलाके में है। उसने अपने छह बच्चों में से ढाई साल के बेटे को पांच हजार रुपये में बेच दिया है। सुकांत सिंह ने स्वीकार किया है कि उसने पिछले तीन दिनों में तीन महिलाओं और एक अन्य पुरुष की मदद से ढाई साल के बच्चे को बेच दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी मां की सालगिरह पर पांच हजार रुपये खर्च किये थे। बताया जाता है कि सुकांत सिंह दिहाड़ी मजदूर और शराबी है। सुकांत सिंह के बेटे ने यह भी बताया कि सुकांत सिंह के अन्य बच्चे बाजार घाट पर भीख मांगकर अपना पेट भर रहे थे। सुकांत ने कहा कि उसके छोटे भाई को उसके पिता ने बेच दिया है। यह खबर नियाली थाना बगीचा बस्ती मुंडासाही क्षेत्र में फैलने के बाद स्थानीय लोगों ने घटना की निंदा की और बच्चे को बचाने की मांग की। स्थानीय लोगों ने आरोपी सुकांत सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि यह बच्चा बिक्री का बड़ा रैकेट काम कर रहा है।

308 पहुंची भूस्खलन से म*रने वालों की संख्या, 200 लोगों की अभी भी तलाश

वायनाड। केरल के वायनाड जिले में हुए कई भूस्खलनों में मरने वालों की संख्या बढक़र 308 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि करीब 200 लोग अब भी लापता हैं। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि राहत एवं बचाव अभियान चल रहा है और अब तक 195 शव तथा 113 मानव अंग बरामद किए जा चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार तडक़े वायनाड में मेप्पडी के पास पहाड़ी इलाकों में भारी भूस्खलन के बाद 213 से अधिक लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इस बीच छह क्षेत्रों में तलाशी के लिए 40 खोज दल गठित किए गए हैं। पहले जोन में अट्टामाला और अरनमाला, दूसरे जोन में मुंडकाई, तीसरे जोन में अमलीमट्टम, चौथे जोन में वेल्लारमाला विलेज रोड, पांचवें जोन में जीवीएचएसएस वेल्लार्मला और छठे जोन में अतिवारा शामिल हैं। प्रत्येक दल में तीन स्थानीय लोग, एक वन विभाग का कर्मचारी और सेना, नौसेना, तटरक्षक बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और अन्य के सदस्य होंगे। ये दल पुलिस और स्थानीय तैराकों के सहयोग से आठ थाना क्षेत्र में आने वाले चालियार नदी क्षेत्रों के 40 किलोमीटर के क्षेत्र में भी खोज करेंगी। पुलिस हेलिकॉप्टर का उपयोग करके समानांतर खोज की जाएगी।

पांच साल में 100 से अधिक वंदे भारत की मिली सौगात, कुल 772 ट्रेनों की हुई शुरुआत; रेल मंत्री

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले पांच सालों में भारतीय रेलवे ने 100 वंदे भारत ट्रेनों समेत 772 ट्रेनें शुरू की हैं। रेलवे ने नई एक्सप्रेस ट्रेन सुपरफास्ट ट्रेनों पैसेंजर मेमो/डेमो ट्रेनों और उपनगरीय ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। उन्होंने कहा कि 102 वंदे भारत ट्रेनें सफलतापूर्वक चल रही हैं। पिछले तीन सालों में किसी भी रेल यात्री की टिकट अनकंफर्म नहीं हुई है।

नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Vande Bharat) ने राज्यसभा को बताया कि पिछले पांच सालों (2019-2024) में भारतीय रेलवे ने 100 वंदे भारत ट्रेनों समेत 772 ट्रेनें शुरू की हैं। उन्होंने बताया कि नई वंदे भारत ट्रेनें किसी ट्रेन की जगह पर नहीं शुरू की गई हैं। यानी इसे शुरू करते हुए किसी मौजूदा ट्रेन को बंद नहीं किया गया है।

सभी श्रेणी के यात्रियों की जरूरतों का रखा गया ध्यानः रेल मंत्री

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को भाजपा सदस्य नीरज शेखर के सवाल के जवाब में बताया कि इन पांच सालों में सभी श्रेणी के यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में नई ट्रेन सेवाएं शुरू की गई हैं। रेलवे ने नई एक्सप्रेस ट्रेन, सुपरफास्ट ट्रेनों, पैसेंजर, मेमो/डेमो ट्रेनों और उपनगरीय ट्रेनों का संचालन शुरू किया है।

देश में कितनी चल रही हैं वंदे भारत ट्रेनें?

उन्होंने कहा कि 102 वंदे भारत ट्रेनें सफलतापूर्वक चल रही हैं। सभी सुपरफास्ट ट्रेनें जैसे राजधानी, शताब्दी भी चलती रहेंगीं। दिल्ली-मुंबई खंड में 31 जोड़ी मेल व एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं। केरल में रेल परियोजनाएं में देरी भूमि अधिग्रहण में अड़चन के कारण हो रही है।

बेबी बर्थ पर रेल मंत्री ने दिया अपडेट

उन्होंने बताया कि ट्रायल के तौर पर लखनऊ मेल में बच्चों के साथ यात्रा करने वाली माताओं के लिए दो बेबी बर्थ भी बनाई गई हैं। पिछले तीन सालों में किसी भी रेल यात्री की टिकट अनकंफर्म नहीं हुई है। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जिसमें यात्रियों ने बड़ी हस्तियों और रेल अधिकारियों के फर्जी लेटर हेड की मदद से इमरजेंसी कोटा हासिल करने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि वन्य जीवों के रेल हादसे को रोकने के लिए रेल विभाग ने हनी बी बजर और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम की व्यवस्था भी की है।

बिना बताए कोवैक्सीन का पेटेंट लने चली थी भारत बायोटेक

नई दिल्ली। कोरोना के विषाणु को निष्क्रिय करने के लिए स्वदेश में विकसित कोवैक्सीन के टीके के पेटेंट हासिल करने के लिए भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड (बीबीआईएल) ने चुपचाप बिना बताए आवेदन कर दिया था, लेकिन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और राष्ट्रीय जीवाणुविज्ञान संस्थान (एनआईवी) के बाद अब तीनों संयुक्त रूप से आवेदक बने हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी।

तृणमूल कांग्रेस के प्रो. सौगत राय ने एक सवाल में कहा कि कोवैक्सीन कोरोना संक्रमण के विरुद्ध दुनिया का सबसे प्रभावी टीका माना गया है, जिसे आईसीएमआर और एनआईवी ने संयुक्त रूप से 35 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया था, लेकिन इस टीके के पेटेंट के लिए बीबीआईएल ने आवेदन किया है और उसमें आईसीएमआर और एनआईवी का उल्लेख नहीं किया है। इस पर सरकार क्या दंडात्मक कार्रवाई करेगी। श्री नड्डा ने कहा कि यह सही है कि कोवैक्सीन के विकास के लिए आईसीएमआर और एनआईवी ने बीबीआईएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। वैक्सीन के विकास के दो भाग थे -एक, विषाणु को अलग थलग करना और दूसरा, विषाणु को निष्क्रिय करना। ये काम आईसीएमआर ने एनआईवी की प्रयोगशाला में किया जिस पर सात करोड़ रुपए की लागत आई और बीबीआईएल ने प्रयोगशाला परीक्षण एवं विकास का काम किया, जिसमें सात करोड़ से अधिक राशि व्यय हुई। बीबीआईएल ने भी इस काम पर 60 करोड़ से अधिक राशि खर्च की है। उन्होंने कहा कि जब हमें पता चला कि बीबीआईएल ने पेटेंट आवेदन में सिर्फ खुद के नाम का उल्लेख किया था, लेकिन जैसे ही सरकार को इसका पता लगा, हमने तुरंत आपत्ति दाखिल की और कहा कि यह तो संयुक्त एमओयू के तहत विकसित किया गया है और तीनों का संयुक्त स्वामित्व है। इस पर बीबीआईएल ने स्वीकार किया कि अनजाने में गलती से वैक्सीन के विकास के लिए जिम्मेदार नामों में आईसीएमआर एवं एनआईवी के नाम छूट गये थे। बहरहाल अब तीनों नाम संयुक्त रूप में पेटेंट के आवेदन में दर्ज हो गए हैं। एक पूरक प्रश्न के उत्तर में श्री नड्डा ने कहा कि कोविड काल में वैक्सीन मैत्री ऑपरेशन के तहत भारत ने 100 देशों को वैक्सीन की आपूर्ति की थी और उनमें से 48 देशों को मुफ्त वैक्सीन भेजी थी।

मेरे खिलाफ ED-CBI रेड की तैयारी, राहुल गांधी ने जताई आशंका

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) उनके खिलाफ छापे मारने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस नेता ने यह जानकारी देते हुए शुक्रवार को बताया कि ईडी के एक अधिकारी ने उन्हें बताया है कि उनके खिलाफ छापे की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने आशंका जताई कि संसद में बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा था कि सरकार विपक्ष और देश के खिलाफ चक्रव्यूह बना रही है और शायद मोदी सरकार को उनका यह बयान पसंद नहीं आया इसीलिए उनके खिलाफ इस तरह की योजना बनाई जा रही है। श्री गांधी ने एक्स पर कहा कि जाहिर है, 2 इन 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। बांहें फैलाकर इंतज़ार कर रहा हूं। चाय और बिस्किट मेरे पास। इस बीच कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में पार्टी के व्हिप मणिकम टैगोर ने स्थगन प्रस्ताव देकर सरकार से ईडी-सीबीआई के दुरुपयोग पर चर्चा करने की मांग की है।

हम रील बनाने वाले नहीं, काम करने वाले : अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि हम केवल रील बनाने वाले नहीं, काम करने वाले लोग हैं। रेल हादसों को लेकर विपक्ष के हंगामे पर नाराजगी जताते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जो लोग यहां चिल्ला रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि सत्ता में रहते हुए 58 साल में वे एक किलोमीटर भी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (एटीपी) क्यों नहीं लगा पाए। संसद में बोलते समय विपक्षी सांसदों के हंगामे से रेल मंत्री नाराज हो गए। इस दौरान विपक्ष के सांसदों से भडक़ते हुए बैठने को कहा। उन्होंने हंगामा करते हुए विपक्षा सांसदों से कहा कि चुप, बैठ जाइए। बैठिए। कुछ भी बोलते हैं। इसके बाद उन्होंने चेयर को संबोधित करते हुए कहा कि ये क्या तरीका है, कुछ भी बीच में बोल देते हैं। रेल मंत्री ने कहा कि आज ये सवाल उठाने की हिम्मत कर रहे हैं, जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थीं, तो हादसा आंकड़ा 0.24 से घटकर 0.19 हो जाने पर ये लोग सदन में ताली बजाते थे और आज जब ये 0.19 से घटकर 0.03 हो गया तो ये इस तरह का दोष लगाते हैं। अश्विनी वैष्णव ने स्पीकर से पूछा कि क्या ये देश ऐसे चलेगा?

श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडविया ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पिछले एक दशक से महिला श्रमबल को बढ़ाने पर काम कर रही है और इसी का परिणाम है कि अब इसमें वृद्धि हो रही है। श्री मांडविया ने प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि मोदी सरकार को जो विरासत में मिला था, उसको बदलने की कोशिश की जा रही है।

विचार

राहुल की जनगणना की मांग के परिणाम

कुलदीप चंद अग्निहोत्री

इस प्रतिवेदन का अगला भाग चौंकाने वाला है, जिसमें आगा खान कहते हैं कि जब भारतीयों को किसी भी संस्थान में उनकी संख्या के बल पर हिस्सेदारी दी जाए तो मुसलमानों को हिस्सेदारी का आधार उनकी संख्या को न माना जाए, बल्कि यह आधार रखा जाए कि मुसलमानों ने ब्रिटिश साम्राज्य की कितनी सेवा की है। आज भी यह शक जाहिर किया जाता है कि आगा खान ने यह प्रतिवेदन स्वयं दिया था या फिर अंग्रेजों ने उसे ऐसा प्रतिवेदन देने के लिए कहा था। ब्रिटिश सरकार ने शायद तभी से देश को विभाजित करने की योजना बनानी शुरू कर दी थी। आगा खान की पिटीशन से वायसराय इतना तो समझ गए थे कि हिंदुओं की जनसंख्या कृत्रिम रूप से कम करने का अवसर है'

वर्ष 1857 की आजादी की पहली लड़ाई के बाद जब ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कम्पनी को अपदस्थ कर भारत का शासन स्वयं संभाल लिया तो उसने 1880 में भारत में पहली बार जनगणना शुरू की। उस समय मरदमशुमारी के लिए हिंदू, मुसलमान और ईसाई के नाम से तीन कॉलम होते थे। सिख, बौद्ध, जैन, ईरानी (पारसी को ईरानी कहा जाता था) की गणना भी अलग होती थी। सन-1900 तक जनगणना इसी हिसाब से चलती रही। इस जनगणना में ब्रिटिश सरकार की यह इच्छा थी कि भारत में विभिन्न मजहबों के लोगों की संख्या कितनी है, यह जान लिया जाए ताकि आगे की रणनीति बनाने में आसानी रहे। अब तक भारत में विदेशी मूल के मजहबों को मानने वालों की संख्या भी अच्छी खासी हो गई थी। विदेशी मूल के तीन मजहब ही भारत में पैर पसार रहे थे। इस्लाम पंथ, एशिया पंथ और मसीही पंथ (क्रिश्चियन)। तीनों का भारत में आगमन मोटे तौर पर आक्रमणकारियों के माध्यम से हुआ था। अरबों, तुर्कों व मुगलों के लंबे शासन काल में इस्लाम पंथ में मतांतरित हो जाने वाले भारतीयों की संख्या भी अब तक काफी हो गई थी। इस्लाम पंथ में मतांतरित भारतीयों के अतिरिक्त एटीएम, यानी विदेशी मूल के मुसलमान भी थे। उस समय ईसाइयों की गिनती तो इस देश में नाममात्र ही थी। केरल में कुछ सीरिआई ईसाई थे जिन्होंने कभी अपने देश में इस्लामी आक्रमणों से भाग कर इस देश में शरण ले रखी थी। इसी प्रकार यूरोपीय जातियों को भी भारत के कुछ हिस्सों पर राज करते हुए लगभग सौ साल हो ही गए थे। इसलिए ईसाई पंथ में मतांतरित भारतीयों की भी कुछ संख्या थी ही। कुछ एंग्लो इंडियन थे। लेकिन इनकी संख्या उस समय निश्चित ही उंगलियों पर गिनी जा सकती थी।

वर्ष 1900 की जनगणना में ईसाई केवल एक प्रतिशत थे और मुसलमान 21 फीसदी थे। मुसलमानों में विदेशी मूल के मुसलमान, देसी मुसलमान और शिया मजहब को मानने वाले भी शामिल थे। इन दोनों के अतिरिक्त शेष भारतीय हिंदू हैं। लेकिन यह भी साफ हो गया था कि ब्रिटिश सरकार ने इस जनगणना में हिंदू शब्द को भौगोलिक न मान कर उसे मजहब का द्योतक शब्द मान लिया था। लेकिन 1885 में कांग्रेस और 1905 में मुस्लिम लीग के गठन से देश में कहीं-कहीं कुछ निकायों में भारतीयों को हिस्सा देने के लिए कानून बनने शुरू हो गए थे। यह चयन मतदान द्वारा होता था। यह ठीक है कि मतदान का अधिकार कुछ गिने-चुने भारतीयों को ही दिया जाता था, लेकिन एक नई पद्धति की शुरुआत तो थी ही। 1909 के अधिनियम में तो विधानपालिकाओं में भी चुनाव द्वारा कुछ स्थान भारतीयों द्वारा भरे जाने थे। इसलिए 1910 की जनगणना से पहले मुसलमानों का एटीएम (अरब, तुर्क, मुगल) मूल का खेमा सक्रिय हो गया। उनकी चिंता थी कि ब्रिटिश सरकार ने इस्लाम पंथी (जिसमें मुसलमान और शिया पंथी दोनों ही शामिल थे) व मसीही के अतिरिक्त अन्य सभी भारतीयों को हिंदू स्वीकार लिया था। इसका अर्थ परोक्ष रूप से यही था कि हिंदू इस देश की भौगोलिक पहचान को ही इंगित करता है। ब्रिटिश सरकार ने मुसलमान और मसीही समुदाय को तो इस भौगोलिक पहचान से अलग कर ही दिया था। लेकिन यदि हिंदू को भी खंडित किया जा सके तो भारत को मानसिक तौर पर घायल करना आसान हो सकता था। 1910 की गणना से पहले एटीएम और ब्रिटिश सरकार ने इस संबंधी पूरी रणनीति तैयार कर ली थी। उसकी शुरुआत आगा खान के ज्ञापन से होती है जो उसने जनगणना के बारे में सरकार को दिया था। लेकिन हिंदू के भौगोलिक आधार को आगे बांटने की जरूरत ब्रिटिश सरकार को क्यों हुई, इसकी चर्चा भीमराव अंबेडकर ने की है। उनका मानना है कि इस प्रश्न का उत्तर मुसलमानों द्वारा आगा खान के नेतृत्व में 1909 में ब्रिटिश सरकार को दिए गए प्रतिवेदन में से मिलेगा।

यह मैमोरंडम आगा खान ने उस समय के वायसराय लार्ड मिंटो को दिया था। आगा खान ने इस प्रतिवेदन में लिखा था कि 1900 की जनगणना में मुसलमानों की संख्या 62 मिलियन है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 1/5 प्रतिशत से लेकर 1/4 प्रतिशत के बीच ठहरता है। आगा खान ने आगे कहा कि जनगणना में से असभ्य समुदाय के लोगों, जिन्हें छिटपुट मजहब और एनिमिस्ट के नाते दर्ज कर रखा है, को निकाल दिया जाए। दूसरे, उन लोगों को जिन्हें हिंदू मान लिया गया है, लेकिन वे हिंदू नहीं हैं, भी निकाल दिया जाए तो देश में हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों की संख्या का प्रतिशत और भी बढ़ जाएगा। अंबेडकर ने वह पूरा मैमोरंडम अपनी किताब 'अछूत कौन थे' में दिया है। लेकिन इस प्रतिवेदन का अगला भाग चौंकाने वाला है, जिसमें आगा खान कहते हैं कि जब भारतीयों को किसी भी संस्थान में उनकी संख्या के बल पर हिस्सेदारी दी जाए तो मुसलमानों को हिस्सेदारी का आधार उनकी संख्या को न माना जाए, बल्कि यह आधार रखा जाए कि मुसलमानों ने ब्रिटिश साम्राज्य की कितनी सेवा की है। आज भी यह शक जाहिर किया जाता है कि आगा खान ने यह प्रतिवेदन स्वयं दिया था या फिर अंग्रेजों ने उसे ऐसा प्रतिवेदन देने के लिए कहा था। ब्रिटिश सरकार ने शायद तभी से देश को विभाजित करने की योजना बनानी शुरू कर दी थी। अंबेडकर ने प्रश्न को आगे और बढ़ाया है। एक बात तो स्पष्ट है कि आगा खान की पिटीशन से वायसराय इतना तो समझ गए थे कि प्रथमया, हिंदू को उसकी भौगोलिकता से काट कर मजहब से पहले ही जोड़ दिया गया है, अब कृत्रिम रूप से उसकी जनसंख्या कम करने का भी अवसर है।

आगा खान ने यह पिटीशन दी थी या ली गई थी, यह बहस का विषय हो सकता है, लेकिन अंग्रेज सरकार ने उसे सही रूप से पकड़ लिया था। इसका तरीका उन्होंने 1910 की जनगणना में निकाला। उन्होंने हिंदू को आगे हिंदू, जनजाति और अछूत नाम से तीन हिस्सों में बांट दिया। उस समय कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। लेकिन ब्रिटिश नीति कामयाब रही और 1947 में देश विभाजित हो गया। अंग्रेजों के चले जाने के बाद कुछ लोगों ने मांग की थी कि जनगणना जाति के आधार पर की जाए, लेकिन पंडित जवाहर लाल नेहरु इसके पीछे छुपी भावना को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया था। लेकिन आज नेहरु की हवेली पर जिन लोगों का कब्जा हो गया है, वे इटली के मैकियावली के सिद्धांतों पर चलते हुए किसी भी कीमत पर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए वे आज 2024 में उसी नीति को फिर से जीवित करना चाहते हैं, जो ब्रिटिश सरकार ने शुरू की थी। राहुल गांधी सलाहकारों की दी हुई स्क्रिप्ट पढने की बजाय यदि बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान सभा के अंतिम सत्र में दिया गया उनका भाषण पढ़ लें तो वे देश की ज्यादा सेवा करेंगे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023